प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विकास विजन | बिहार की नई औद्योगिक उड़ान | स्क्रीन सीमित हो, सीखने की दुनिया असीमित हो-मेधा रूपम

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 | अंक 9 | सितंबर 2026 | ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

विकास की सोच • नवाचार की राह • समृद्ध भारत का निर्माण

हिंदी मासिक पत्रिका

जापान का भरोसा यूपी की उड़ान

तकनीक जापान की, ताकत उत्तर प्रदेश की—साथ मिलकर खुल रहे विकास के नए दरवाजे

निवेश से उद्योग | उद्योग से रोजगार
तकनीक से कौशल | संस्कृति से रिश्ते | साझेदारी से विकास



AI से बदलेगा हरियाणा का भविष्य



युवा शक्ति से विकसित उत्तर प्रदेश की ओर



कौशल, नवाचार और स्टार्टअप से बन रहा नया उत्तर प्रदेश

हरियाणा में स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार



वर्ल्ड बैंक के सहयोग से डिजिटल सुशासन, कौशल विकास और स्वच्छ पर्यावरण की नई इबारत

ग्रामीण विकास से बदलती तस्वीर, खुद पर भरोसा, भविष्य पर भरोसा



सशक्त नारी, समृद्ध भारत की नई तस्वीर

नीति — सकारात्मक परिवर्तन
नवाचार — नए विचार, नए समाधान
साझेदारी — मजबूत सहयोग, उज्ज्वल भविष्य
विकास — समृद्धि की ओर निरंतर कदम

SARDAR PATEL POST GRADUATE INSTITUTE OF DENTAL & MEDICAL SCIENCES

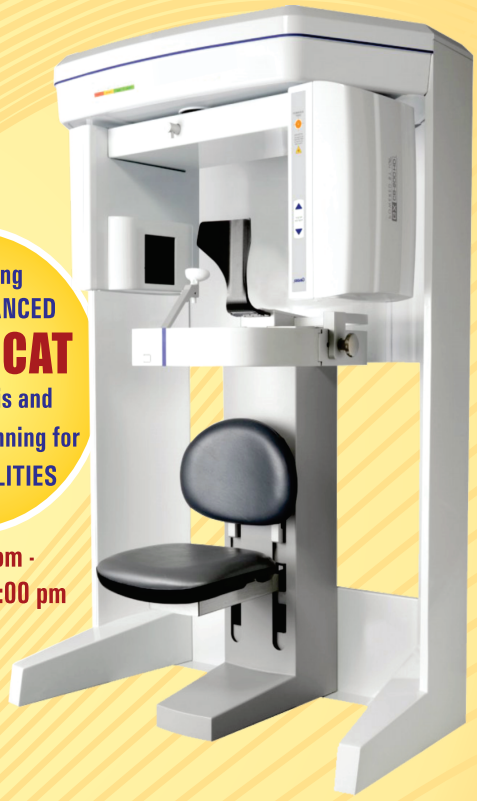
(Recognized By Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India and Dental Council of India, New Delhi)

COURSES OFFERED :

- B.D.S.
- M.D.S. (ALL SPECIALITIES)
- DIPLOMA IN IMPLANTOLOGY
- PARA DENTAL COURSES
- DENTAL HYGIENIST
- DENTAL MECHANIC

FACILITIES OFFERED :

- SEMINAR ROOM, LIBRARY & MUSEUMS
- LABORATORY & COMPUTER LAB
- Wi-Fi ENABLED CAMPUS
- AUDITORIUM/CONFERENCE HALL
- HOSTELS & TRANSPORTATION
- SPORTS COMPLEX
- CAFETARIA, CAFE COFFEE DAY
- HOSPITAL



introducing
MOST ADVANCED
CBCT i-CAT
for Diagnosis and
Treatment Planning for
ALL SPECIALITIES

- Open From -
9:00 am to 9:00 pm



"ADVANCED
DENTISTRY
AT ACADEMIC LEVEL"

"CHAUDHARY VIHAR" SARDAR PATEL CHOWK, RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226025

0522-2442030-35, 9451188900, 99194 36362

इस अंक में





13
एआई से बदलेगा हरियाणा का भविष्य



26
जापान का भरोसा, यूपी की उड़ान
तकनीक जापान की, ताकत उत्तर प्रदेश की—साथ मिलकर खुल रहे विकास के नए दरवाजे



18
युवा शक्ति से विकसित उत्तर प्रदेश की ओर



22
मिंजर की सुनहरी डोर में सजा हिमाचल का गौरव



24
सशक्त नारी, समृद्ध उत्तराखंड की नई तस्वीर

निर्माणशाला टाइम्स
हिंदी मासिक पत्रिका
मूल्यः 20 रुपये, सितंबर 2026
वर्ष-7 अंकः 9, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह
संपादक
अहमद हसन
सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तर प्रदेश-	**सी.बी. सिंह**
उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय
मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।
पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)
RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

लोकल की आवाज़, आत्मनिर्भर भारत का विश्वास

हमारी खरीदारी की छोटी-सी पसंद, किसी भारतीय परिवार के बड़े सपने को दे सकती है उड़ान

त्योहारों का मौसम आते ही बाजार रोशनी से जगमगा उठते हैं। घरों में खुशियां दस्तक देती हैं और खरीदारी का उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन इस रौनक के बीच एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए— **हमारी खरीदारी की रोशनी आखिर किसके घर तक पहुंच रही है?**

यही सवाल **'लोकल फॉर वोकल'** को महज एक अभियान नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सोच बनाता है।

भारत की असली ताकत उसके करोड़ों मेहनतकश हाथों में है। मिट्टी को आकार देता कुम्हार, करघे पर सपने बुनता बुनकर, हस्तशिल्प को जीवंत करता कारीगर, खेतों में मेहनत करता किसान, घर से उद्यम खड़ा करती महिला और अपने छोटे व्यवसाय को नई ऊंचाई देने का सपना देखता युवा—ये सभी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं।

जब हम इनके उत्पाद खरीदते हैं, तो हम केवल कोई वस्तु नहीं खरीदते। **हम उनके श्रम, हुनर और आत्मसम्मान को सम्मान देते हैं।**

'लोकल फॉर वोकल' का अर्थ केवल स्थानीय उत्पादों को खरीदना नहीं है। इसका अर्थ है— **भारतीय प्रतिभा पर भरोसा करना, स्थानीय उद्यम को अवसर देना और अपने उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लेना।**

आज आवश्यकता है कि स्थानीय उत्पादों को गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, बेहतर पैकेजिंग और डिजिटल बाजार से जोड़ा जाए। हमारा कारीगर केवल स्थानीय बाजार का हिस्सा न रहे, बल्कि उसके हाथों का हुनर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाए।

आखिर हमारा लक्ष्य केवल 'लोकल खरीदना' नहीं होना चाहिए, बल्कि **लोकल को ब्रांड बनाना और लोकल को ग्लोबल बनाना** होना चाहिए।

यह बदलाव केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। सरकार नीतियां बना सकती है, संस्थाएं सहयोग दे सकती हैं, लेकिन बाजार की दिशा तय करने की शक्ति उपभोक्ता के हाथ में है।

हमारी जेब में रखा पैसा केवल मुद्रा नहीं, हमारी पसंद की शक्ति है।

त्योहार पर जब हम किसी कुम्हार का दीपक खरीदते हैं, तो उसके घर की रोशनी बढ़ती है। किसी महिला समूह का उत्पाद खरीदते हैं, तो उसके आत्मविश्वास को ताकत मिलती है। किसी छोटे उद्यमी से खरीदारी करते हैं, तो उसके व्यवसाय को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

इसलिए इस त्यौहारी सीजन एक छोटा-सा संकल्प लें— **जहां संभव हो, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें, उनके बारे में दूसरों को बताएं और भारतीय हुनर को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं।**

क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना बड़े उद्योगों से ही नहीं, **छोटे-छोटे उद्यमों और करोड़ों भारतीय हाथों की मेहनत से पूरा होगा।** ■

इस बार त्योहार पर सिर्फ घर न सजाएं— किसी भारतीय हुनर का भविष्य भी सजाएं। लोकल के लिए वोकल बनें, लोकल पर विश्वास करें और लोकल को ग्लोबल बनाने में सहभागी बनें।



जेवर से खुलेगा विकास का नया द्वार

मेडिकल हब, फार्मा क्लस्टर, ताइवान सिटी और यूनिवर्सिटी टाउनशिप से आकार लेगा नया औद्योगिक इकोसिस्टम

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई तस्वीर अब जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में तेजी से आकार ले रही है। प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले इस क्षेत्र को केवल औद्योगिक निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि **स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, तकनीक, खेल और आधुनिक परिवहन सुविधाओं से युक्त एकीकृत आर्थिक क्षेत्र** बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मेडिकल हब से स्वास्थ्य क्षेत्र को नई पहचान

सेक्टर-13 और 14 में लगभग **500 एकड़ में मेडिकल हब** विकसित करने की मंजूरी क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इकोसिस्टम के लिए बड़ा अवसर है। इसके साथ सेक्टर-14 में **480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप** विकसित करने की योजना उच्च शिक्षा और शोध के नए केंद्र के रूप में क्षेत्र की क्षमता बढ़ाएगी।

मेडिकल संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध केंद्रों और हेल्थकेयर सेवाओं के एक साथ विकसित होने से चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।



फार्मा और मेडिकल डिवाइस: आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

सेक्टर-06 में **100 से 125 एकड़ में फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर** विकसित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश को फार्मा विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम पहल है। जीएमपी मानकों के अनुरूप दवा निर्माण इकाइयों से निवेश, उत्पादन और रोजगार को गति मिलने की उम्मीद है।

इसी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के भीतर



अंतरराष्ट्रीय स्तर की **मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग फैसिलिटी** स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। इससे भारतीय निर्माताओं और एमएसएमई इकाइयों को परीक्षण एवं कन्फॉर्मिटी असेसमेंट के लिए देश में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ताइवान सिटी से तकनीकी निवेश को मिलेगा मंच

सेक्टर-06 में **300 एकड़ भूमि पर ताइवान सिटी** विकसित करने के लिए भूमि आरक्षित करने का निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीक और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की संभावनाओं को मजबूत करता है। इससे क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों, सप्लाई चेन और तकनीकी कौशल आधारित रोजगार का इकोसिस्टम विकसित हो सकता है।

एयरपोर्ट के साथ मजबूत होगी कनेक्टिविटी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए सेक्टर-23सी में **अंतर्राज्यीय बस अड्डे** के लिए भूमि चिन्हित करने का फैसला कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और नए विकसित हो रहे शहरी केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क मजबूत होने से यात्रियों, उद्यमियों और कामगारों को सुविधा मिलेगी।

वहीं सेक्टर-23डी में लगभग **50 एकड़ में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम** की योजना खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र को बड़े खेल आयोजनों के लिए तैयार कर सकती है।

किसानों के लिए बेहतर बाजार और बढ़ी भूमि क्रय दर

सेक्टर-34 में करीब **36 एकड़ में आधुनिक मंडी** विकसित करने की योजना कृषि उत्पादों के विपणन, भंडारण और व्यापार को व्यवस्थित करने में मददगार हो सकती है। दूसरी ओर, किसानों से सहमति के आधार पर भूमि खरीद की दर **4,300 से बढ़ाकर 4,558 रुपये प्रति वर्ग मीटर** किए जाने से भूमि उपलब्ध कराने वाले किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है।

वित्तीय मजबूती से विकास परियोजनाओं को आधार

यीडा की वित्तीय स्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 31 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां **1,853.74 करोड़ रुपये** रहीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.25 प्रतिशत अधिक हैं। मजबूत वित्तीय आधार से भूमि, आधारभूत ढांचे और भविष्य की विकास परियोजनाओं को गति देने में मदद मिल सकती है।

जेवर बन रहा है नए उत्तर प्रदेश की विकास धुरी

यीडा की 92वीं बोर्ड बैठक के फैसलों को एक साथ देखा जाए तो जेवर क्षेत्र में विकास का एक व्यापक मॉडल उभरता है— **एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, उद्योगों के लिए भूमि, फार्मा और मेडिकल डिवाइस, वैश्विक तकनीकी निवेश, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल और कृषि बाजार।**

यही एकीकृत दृष्टिकोण जेवर को आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास क्षेत्रों में शामिल कर सकता है। औद्योगिक निवेश के साथ यदि स्थानीय कौशल विकास, एमएसएमई भागीदारी और रोजगार सृजन को समान गति मिलती है, तो इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक व्यापक रूप से पहुंच सकता है।

यीडा क्षेत्र में हो रहा यह विस्तार केवल नई परियोजनाओं का जुड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की आधारशिला है जहां उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और आधुनिक अवस्थापना एक ही विकास-परिसर में साथ आगे बढ़ेंगे। ■

जब ग्लोबल टेक्नोलॉजी ने चुनी ग्रेटर नोएडा की धरती

Hollyland की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भारत के 'क्रिएटर इकोनॉमी' को मिला नया माइक्रोफोन

'मेड इन इंडिया' से आगे बढ़कर 'क्राफ्टेड इन इंडिया' की नई कहानी



भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलती तस्वीर में ग्रेटर नोएडा से एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है। **MSM Electronics India Pvt. Ltd.** द्वारा ग्रेटर नोएडा में **Hollyland के क्रिएटर माइक्रोफोन्स के स्थानीय उत्पादन** की शुरुआत केवल एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं, बल्कि भारत में वैश्विक तकनीक और स्थानीय विनिर्माण क्षमता के बढ़ते संगम का प्रतीक है।

20 अगस्त 2026 को आयोजित उद्घाटन समारोह में **MSM Group के चेयरमैन श्री मोहिंदर सिंह मलिक, MSM Electronics India Pvt. Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रभजोत सिंह मलिक तथा राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।** समारोह में Hollyland, MSM Electronics, GITPL तथा टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।



ग्रेटर नोएडा से उठी नई विनिर्माण आवाज

आज भारत केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि वैश्विक कंपनियों के लिए तेजी से विकसित होता हुआ **मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन** भी बन रहा है।

Hollyland वायरलेस ऑडियो और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है। इसके उत्पाद कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फिल्ममेकर्स, ब्रॉडकास्टर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के बीच इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऐसे समय में भारत में इसके माइक्रोफोन्स का स्थानीय उत्पादन शुरू होना देश की तेजी से बढ़ती **Creator Economy** के लिए भी महत्वपूर्ण है।

YouTube से लेकर Instagram, short-form video, livestreaming और podcasts तक—डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों को कंटेंट क्रिएशन से जोड़ा है। इस बढ़ते बाजार के लिए प्रोफेशनल और भरोसेमंद ऑडियो उपकरणों की मांग भी लगातार बढ़ रही है।



मुख्य अतिथि का संदेश
श्री अरुण सिंह, राज्यसभा सांसद

“एक ऐसा अवसर, जो भारत की नई औद्योगिक पहचान को रेखांकित करता है”

ग्रेटर नोएडा में Hollyland की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ इस बात का संकेत है कि वैश्विक टेक्नोलॉजी ब्रांड भारत की विनिर्माण क्षमता और बाजार की संभावनाओं को गंभीरता से देख रहे हैं।

समारोह में राज्यसभा सांसद **श्री अरुण सिंह मुख्य अतिथि** के रूप में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति ने इस औद्योगिक पहल को विशेष महत्व प्रदान किया।

निर्माणशाला टाइम्स के लिए यह पहल इसलिए खास है क्योंकि यह केवल एक कंपनी के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जहां वैश्विक तकनीक स्थानीय प्रतिभा, स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाजार से जुड़ रही है।

एक फैक्ट्री, अनेक संभावनाएं

स्थानीय उत्पादन का प्रभाव केवल असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ **कंपोनेंट सोर्सिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग और रोजगार** जैसे क्षेत्रों में भी अवसर पैदा होते हैं।

यही वजह है कि Hollyland और MSM Electronics की साझेदारी को वैश्विक तकनीक और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के बीच विकसित होते नए मॉडल के रूप में देखा जा सकता है।

ग्रेटर नोएडा—भारत के टेक मैन्युफैक्चरिंग मैप पर और मजबूत

मजबूत सप्लायर इकोसिस्टम, कुशल मानव संसाधन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता के कारण ग्रेटर नोएडा देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। Hollyland की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि इस क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक पहचान को और मजबूत करती है।

यह शुरुआत केवल माइक्रोफोन निर्माण की नहीं यह उस नए भारत की आवाज है—
जहां Global Brand भारत में Manufacturing Partner खोजता है, जहां Technology भारतीय धरती पर आकार लेती है, जहां Creator Economy उद्योग को नई दिशा देती है, और जहां Greater Noida वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करता है।
Hollyland की यह पहल आने वाले वर्षों में भारत के क्रिएटर-टेक्नोलॉजी सेक्टर की बढ़ती संभावनाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है।
'The future of creator technology is increasingly being built in India.'
ग्रेटर नोएडा में 20 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह Hollyland की तकनीक को भारतीय उपभोक्ताओं के और करीब लाने के साथ-साथ भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है।



विशेष बातचीत

'भारत हमारे लिए सिर्फ बाजार नहीं, भविष्य की संभावनाओं का केंद्र है'

श्री प्रभजोत सिंह मलिक | Managing Director, MSM Electronics India Pvt. Ltd.

प्रश्न 1: Hollyland ने भारत को अपने भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बाजार क्यों माना?

श्री प्रभजोत सिंह मलिक: भारत Hollyland के लिए केवल अपनी विशाल आबादी के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की डिजिटल और क्रिएटर इकोनॉमी के विकास में हमें मजबूत दीर्घकालिक संभावनाएं दिखाई देती हैं।

प्रश्न 2: Hollyland के लिए भारत की Creator Economy इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

श्री प्रभजोत सिंह मलिक: YouTube, Instagram, short-form video, livestreaming, podcasts और दूसरे डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में लोग कंटेंट क्रिएटर के रूप में आगे आ रहे हैं।

प्रश्न 3: भारत में Wireless Microphones को आप महत्वपूर्ण Growth Opportunity क्यों मानते हैं?

श्री प्रभजोत सिंह मलिक: भारत में बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ क्रिएटर इकोसिस्टम है। इसलिए वायरलेस माइक्रोफोन कैटेगरी में भारत के बाजार के लिए दीर्घकालिक संभावनाएं बेहद मजबूत हैं।

प्रश्न 4: Hollyland के लिए 'Crafted in India' का क्या अर्थ है?

श्री प्रभजोत सिंह मलिक: यह भारतीय बाजार के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही हमारा उद्देश्य भारतीय प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के साथ और अधिक मजबूत एवं करीबी संबंध बनाना है।

प्रश्न 5: Hollyland भारत में Localisation को किस रूप में देखता है?

श्री प्रभजोत सिंह मलिक: आने वाले समय में कंपनी अपने स्थानीय ऑपरेशंस, मार्केट गतिविधियों, चैनल पार्टनरशिप तथा क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के साथ संबंधों को लगातार मजबूत करेगी।





अंगदान जागरूकता में राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य

राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान ने बढ़ाया मानवता, जनभागीदारी और स्वास्थ्य सेवाओं का गौरव

'**अंगदान—जीवन का सबसे बड़ा उपहार**' केवल एक संदेश नहीं, बल्कि संवेदनशील समाज की पहचान है। इसी मानवीय सोच को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में राजस्थान ने देशभर में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राजस्थान ने **अंगदान संकल्प अभियान** में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य की प्रभावी स्वास्थ्य नीति, जन-जागरूकता अभियानों और समाज की सक्रिय भागीदारी का सशक्त प्रमाण है।

नई दिल्ली में आयोजित **16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे** समारोह में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत **नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO)** द्वारा राजस्थान को '**स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस**' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि लाखों लोगों में जीवन बचाने की भावना को सशक्त बनाने वाले प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है।

राजस्थान सरकार द्वारा अंगदान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर जनसंपर्क अभियान, स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, चिकित्सकों की सक्रिय भूमिका तथा समाज की सहभागिता ने इस सफलता की मजबूत नींव रखी है। राज्य में विकसित संस्थागत व्यवस्था ने अंगदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और विश्वासपूर्ण बनाया है, जिससे लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है।

निर्माणशाला टाइम्स राजस्थान की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राज्य सरकार, चिकित्सा समुदाय तथा उन सभी जागरूक नागरिकों को हार्दिक बधाई देता है, जिन्होंने अंगदान जैसे महापुण्य कार्य को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह सम्मान केवल राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत की मानवीय संवेदनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था की सशक्त उपलब्धि का प्रतीक है।



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री **श्री गजेंद्र सिंह खींवसर** ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री **श्री भजनलाल शर्मा** के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी स्वास्थ्य नीतियों और संवेदनशील प्रशासन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अंगदान किसी भी व्यक्ति द्वारा मानवता को दिया जाने वाला सबसे महान उपहार है, जो अनेक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्रदान करता है।

वहीं, प्रमुख शासन सचिव **श्रीमती गायत्री राठौड़** ने इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, **राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO)**, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों की सफलता बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का लक्ष्य अंगदान जागरूकता को और अधिक व्यापक बनाते हुए प्रत्येक नागरिक को इस महाअभियान से जोड़ना है।

राजस्थान बना राष्ट्रीय प्रेरणा

राजस्थान की यह उपलब्धि देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। यह दर्शाती है कि जब सरकार, चिकित्सा संस्थान और समाज मिलकर कार्य करते हैं, तब स्वास्थ्य सेवाओं में असाधारण परिवर्तन संभव होता है। अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और मानवता का ऐसा सेतु है, जो किसी परिवार की बुझती उम्मीदों को फिर से रोशन कर सकता है।

आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक अंगदान के महत्व को समझे, भ्रांतियों से ऊपर उठकर जागरूकता फैलाए और इस मानवीय अभियान का सहभागी बने। क्योंकि एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। ■



उत्तर प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई उड़ान

फ्लिपकार्ट–उत्तर प्रदेश साझेदारी: एमएसएमई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आत्मनिर्भर उद्यमिता का नया अध्याय

निर्माणशाला टाइम्स संपादकीय टीम

उत्तर प्रदेश आज केवल जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। बेहतर कानून-व्यवस्था, निवेश अनुकूल नीतियों, आधुनिक आधारभूत संरचना और डिजिटल नवाचारों ने राज्य को उद्योग एवं ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** और फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी **कल्याण कृष्णमूर्ति** की हालिया मुलाकात भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।

फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि कंपनी राज्य की विकास यात्रा में केवल एक व्यावसायिक भागीदार नहीं, बल्कि नवाचार, तकनीक और रोजगार सृजन की सहभागी बनकर आगे बढ़ना चाहती है। पिछले डेढ़ दशक में उत्तर प्रदेश में फ्लिपकार्ट के कारोबार का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि राज्य में **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपभोक्ता बाजार और उद्यमशीलता** का वातावरण लगातार मजबूत हुआ है।

एमएसएमई को मिलेगा डिजिटल बाजार का व्यापक विस्तार

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े **एमएसएमई नेटवर्क** वाले राज्यों में अग्रणी है। **हस्तशिल्प, हथकरघा, ओडीओपी उत्पाद, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, खेल सामग्री और पारंपरिक कुटीर उद्योग** राज्य की आर्थिक पहचान हैं। फ्लिपकार्ट जैसे राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अधिकाधिक उद्यमों के जुड़ने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** द्वारा अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के **एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर दिया गया विशेष बल** स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे छोटे उद्यमियों की आय बढ़ेगी,

> **उत्तर प्रदेश का भविष्य केवल बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि लाखों छोटे उद्यमियों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और युवाओं की भागीदारी से निर्मित होगा। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बढ़ता सहयोग इसी परिवर्तन की आधारशिला है। फ्लिपकार्ट जैसी अग्रणी डिजिटल कंपनी की सक्रिय भागीदारी राज्य के एमएसएमई, महिला उद्यमियों, युवाओं और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।**

विपणन की लागत कम होगी तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित होगा नया उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशासनिक एवं औद्योगिक विकास को नई प्राथमिकता दे रही है। फ्लिपकार्ट द्वारा राज्य के **एआई विजन** का सहभागी बनने की इच्छा इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में **ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सप्लाई चेन** तथा स्मार्ट उपभोक्ता सेवाओं में नई संभावनाएँ विकसित होंगी। एआई आधारित समाधान न केवल व्यापार को अधिक प्रभावी बनाएंगे, बल्कि उत्पादकता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएंगे। यह पहल युवाओं के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल और रोजगार के नए द्वार खोलेगी।

रोजगार और उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम

डिजिटल कॉमर्स का विस्तार केवल ऑनलाइन बिक्री तक सीमित नहीं है। इसके साथ **वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, फिनटेक और तकनीकी सेवाओं** जैसे अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह परिवर्तन **आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप संस्कृति** को मजबूत करने वाला साबित होगा।

'मेक इन यूपी' से 'मार्केट टू इंडिया' तक

उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियां, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर नीति, लॉजिस्टिक्स पार्क और निवेश अनुकूल वातावरण अब डिजिटल मार्केटप्लेस के साथ मिलकर राज्य को नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर रहे हैं। यदि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मंचों का सशक्त सहयोग मिलता है, तो **'मेक इन यूपी' का सपना 'मार्केट टू इंडिया एंड ग्लोबल'** की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ■

बस्तर से विकसित छत्तीसगढ़ तक

प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विकास विजन

बस्तर के कायाकल्प से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़



नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की हालिया मुलाकात केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भविष्य की विकास रूपरेखा प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई। इस बैठक में बस्तर के समग्र विकास, औद्योगिक निवेश, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल सुशासन जैसे अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यह संवाद स्पष्ट संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

बस्तर : संघर्ष से समृद्धि की ओर

एक समय नक्सल हिंसा के कारण चर्चा में रहने वाला बस्तर आज विकास, विश्वास और परिवर्तन का प्रतीक बनता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ' **नियद नेल्ला नार 2.0' तथा 'बस्तर मुन्ने'** जैसी योजनाओं के माध्यम से हजारों गांवों तक शासन की योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंच रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, आवास, वनाधिकार और वित्तीय समावेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे बस्तर के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई ऊर्जा

राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग **10,500 करोड़ रुपये** की गैस आधारित यूरिया परियोजना राज्य के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर निर्माण, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा यह प्रमाणित करती है कि प्रभावी नेतृत्व, सुशासन, निवेश-अनुकूल नीतियां और जनभागीदारी के माध्यम से कठिन चुनौतियों को भी विकास के अवसरों में बदला जा सकता है। बस्तर का बदलता स्वरूप केवल एक क्षेत्र का परिवर्तन नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक विश्वास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते नए भारत की प्रेरक कहानी है। यदि प्रस्तावित परियोजनाओं को केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी औद्योगिक, कृषि, तकनीकी और निवेश केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है।

तथा मेडिकल उपकरण उद्योगों की स्थापना छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक पहचान प्रदान कर रही है। लगभग **8 लाख करोड़ रुपये** के निवेश प्रस्ताव राज्य के प्रति उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य : विकास की मजबूत आधारशिला

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े **421 विद्यालयों** का पुनः संचालन तथा नए एजुकेशन सिटी का विकास यह दर्शाता है कि सरकार आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं **मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान** के अंतर्गत लाखों लोगों की स्वास्थ्य जांच तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। रायपुर अथवा बस्तर में **ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA)** की स्थापना का प्रस्ताव पारंपरिक चिकित्सा एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

ऊर्जा, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी का विस्तार

दुर्गम क्षेत्रों के **461 गांवों** को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने का प्रयास ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जगदलपुर-रावघाट रेललाइन, सड़क नेटवर्क, हवाई संपर्क का विस्तार तथा सिंचाई परियोजनाओं का विकास यह संकेत देता है कि बस्तर अब देश के विकास मानचित्र पर नई गति से आगे बढ़ रहा है। मजबूत आधारभूत संरचना निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय विकास की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी।

महिला सशक्तिकरण और सुशासन का नया मॉडल

राज्य में **10 लाख से अधिक महिलाओं का 'लखपति दीदी'** बनना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता की सफलता का सशक्त उदाहरण है। वहीं डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में सेवा सेतु पोर्टल, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, वीडियो केवाईसी आधारित रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी पहलें सुशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और जन-केंद्रित बना रही हैं।

एआई आधारित प्रशासन : भविष्य की तैयारी

500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रहा है। यह पहल सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ डिजिटल इंडिया अभियान को भी नई गति प्रदान करेगी।

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान

विश्व प्रसिद्ध **बस्तर दशहरा,** चित्रकोट जलप्रपात और तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन विकास का यह संतुलन क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार करेगा। ■

एआई से बदलेगा हरियाणा का भविष्य

वर्ल्ड बैंक के सहयोग से डिजिटल सुशासन, कौशल विकास और स्वच्छ पर्यावरण की नई इबारत

'तकनीक तभी सार्थक है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे'

इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा-आधारित प्रशासन और डिजिटल नवाचार को जनहित से जोड़ते हुए सुशासन का एक नया मॉडल विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ऐसी पहल शुरू की है, जो आने वाले वर्षों में हरियाणा को देश के सबसे आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में



स्थापित कर सकती है।

डिजिटल हरियाणा की ओर निर्णायक कदम

चंडीगढ़ में वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि उसे आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का माध्यम बनाना है। AI आधारित शासन व्यवस्था से सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेंगी।

PPP 2.0 : सामाजिक न्याय का और अधिक सशक्त माध्यम

हरियाणा का परिवार पहचान पत्र (PPP) पहले ही देशभर में एक सफल डिजिटल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अब **PPP 2.0** के माध्यम से इसे और अधिक स्मार्ट, आधुनिक एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के समयबद्ध रूप से पहुंच सके।

डेटा लेक और एआई से मजबूत होगा निर्णय तंत्र

राज्य सरकार व्यापक **डेटा एक्सचेंज पॉलिसी** तथा **डेटा लेक** विकसित कर विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के समन्वय को मजबूत करेगी। इससे नीतियां अधिक सटीक तथ्यों पर आधारित होंगी, प्रशासनिक निर्णयों में गति आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

एआई गुरुकुल : युवाओं के लिए भविष्य की तैयारी

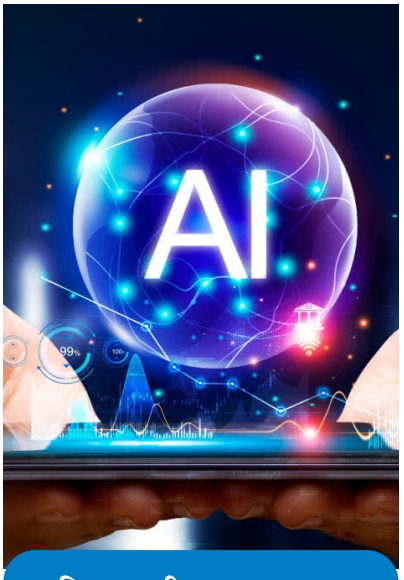
हरियाणा सरकार का प्रस्तावित **AI Gurukul** युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा। प्रत्येक जिले में कौशल विकास केंद्र स्थापित कर उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश का युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगा।

हरियाणा का अपना एआई मॉडल

राज्य सरकार एक ऐसे समर्पित AI मॉडल की दिशा में कार्य करना चाहती है, जो हरियाणा के कानूनों, नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझते हुए अधिकारियों को त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे। इससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सुधार होगा।

स्वच्छ हवा की दिशा में एआई आधारित पहल

वायु प्रदूषण आज शहरी विकास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार **AI आधारित Air Quality Decision Support System** विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। आधुनिक तकनीकों की सहायता से प्रदूषण के स्रोतों का वैज्ञानिक विश्लेषण, पूर्वानुमान और प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। यह पहल हरियाणा के क्लीन एयर मिशन को नई गति प्रदान करेगी।



हरियाणा की यह पहल स्पष्ट करती है कि भविष्य का विकास केवल भौतिक अवसंरचना से नहीं, बल्कि डेटा, डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी उपयोग से तय होगा। यदि AI का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाए, तो यह सुशासन का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है।

स्टार्टअप्स बनेंगे परिवर्तन के साझेदार

वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित **AI Sandbox** नवाचार को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच बनकर उभरा है। हाल ही में आयोजित इनोवेशन चैलेंज में लगभग **250 स्टार्टअप्स एवं कंपनियों** की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा तेजी से नवाचार की राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन नवाचारों को सरकारी विभागों में लागू कर नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की योजना राज्य सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

वैश्विक मंच पर हरियाणा की डिजिटल पहचान

अक्टूबर में कोरिया में आयोजित होने वाले **कोरिया डिजिटल समिट** में हरियाणा के सहयोग से विकसित **AI Sandbox** का प्रदर्शन किया जाना राज्य के लिए गौरव का विषय है। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल क्षमता और हरियाणा की प्रशासनिक नवाचार यात्रा को वैश्विक पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण अवसर है।

वर्ल्ड बैंक के सहयोग और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही यह पहल न केवल हरियाणा के विकास को नई दिशा देगी, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी डिजिटल सुशासन का प्रेरणादायी मॉडल सिद्ध हो सकती है। यह अभियान एक ऐसे भारत की परिकल्पना को मजबूत करता है, जहां तकनीक का वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। ■

'आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है'

उत्तराखंड में उद्योग-व्यापार को नई उड़ान—29 हजार से अधिक एमएसएमई ने बदली आर्थिक तस्वीर





उत्तराखंड की विकास यात्रा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच रही है, जहां पहाड़ की प्रतिभा, मैदान की औद्योगिक क्षमता और प्रदेश के स्थानीय उत्पाद मिलकर आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** का स्पष्ट विजन है कि उत्तराखंड में व्यापार और उद्योग केवल आर्थिक गतिविधियां न रहें, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास के मजबूत माध्यम बनें। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के व्यापारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापार-जगत की समस्याओं और सुझावों को सुना तथा उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि **व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।**

29 हजार से अधिक नई एमएसएमई—रोजगार के 1.27 लाख अवसर

प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में **29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं,** जिनसे लगभग **1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार** मिला है। यह उपलब्धि बताती है कि उत्तराखंड में युवा अब केवल नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं, बल्कि स्वयं रोजगार सृजन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने कारोबार की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को प्राथमिकता दी है। निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए **'निवेश मित्र'** व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वहीं **26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं सिंगल विंडो पोर्टल पर ऑनलाइन** उपलब्ध कराई गई हैं।

'मेड इन उत्तराखंड' बनेगा भरोसे और गुणवत्ता की पहचान

उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और ग्रामीण उद्यमिता को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए **'वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट'** जैसी पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय उत्पादों को केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में मजबूत ब्रांड बनाया जाए।

फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, जबकि पर्वतीय जिलों में भी छोटे उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर है।

स्टार्टअप और वेंचर फंड से युवाओं को नई ताकत

युवाओं को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई है तथा **200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड** स्थापित किया गया है। उद्देश्य है कि पहाड़ का युवा पलायन की मजबूरी से बाहर निकलकर अपने गांव से ही ऐसा उद्यम खड़ा करे, जो देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है—**'व्यापार की प्रगति में ही प्रदेश की प्रगति निहित है।'** सरकार उद्योगों को बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी और भागीदार बनाना चाहती है। उत्तराखंड की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि छोटे दुकानदार, किसान, शिल्पकार, स्टार्टअप, स्थानीय उद्यमी और युवा व्यवसायियों की सामूहिक ऊर्जा से बनेगी। यही सहभागिता प्रदेश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में आगे ले जा रही है। **'आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है।'** मुख्यमंत्री का यह विश्वास आज उत्तराखंड के व्यापार और उद्योग जगत के लिए भरोसे का संदेश ही नहीं, बल्कि विकासकी नई साझेदारी का संकल्प बनता दिखाई दे रहा है। ■



ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक विकास को नई गति
संवाद, समाधान और सुशासन की सशक्त पहल

ग्रेटर नोएडा आज देश के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उद्योगों की आवश्यकताओं को समझते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रशासन और उद्यमियों के बीच संवाद को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उद्योगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि औद्योगिक विकास केवल नई परियोजनाओं से नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाओं और उत्तरदायी प्रशासन से भी सुनिश्चित होता है। प्राधिकरण के सीईओ के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में **एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव** एवं **एसीईओ सुमित यादव** ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह पहल उद्योग-अनुकूल प्रशासन और सहभागी विकास मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है।

बैठक में सीवर, ड्रेनेज, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जलभराव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से **सिंगल विंडो सिस्टम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) तथा एकमुश्त समाधान योजना (OTS)** जैसी मांगों पर सकारात्मक विचार-विमर्श उद्योगों के लिए भविष्य में बड़ी राहत का आधार बन सकता है।

औद्योगिक विकास तभी स्थायी बनता है जब प्रशासन और उद्योग जगत साझेदार की भूमिका निभाएं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह पहल इसी सकारात्मक सोच का परिचायक है, जहाँ समस्याओं पर चर्चा के साथ-साथ उनके व्यावहारिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह मॉडल उत्तर प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत सिद्ध हो सकता है।

ईकोटेक-3 को मॉडल इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव औद्योगिक अवसंरचना को नई पहचान देने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं प्रत्येक औद्योगिक सेक्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित होने से सम्मेलन, प्रशिक्षण, निवेशकों की बैठकें और व्यावसायिक गतिविधियाँ अधिक सुव्यवस्थित एवं आधुनिक बन सकेंगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वेंडिंग ज़ोन का विकास तथा मजबूत ड्रेनेज नेटवर्क जैसी व्यवस्थाएँ न केवल उद्योगों के संचालन को सुगम बनाएंगी, बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित औद्योगिक वातावरण भी तैयार करेंगी। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और नए उद्योगों को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया यह संवाद आधारित दृष्टिकोण **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', उद्योग हितैषी प्रशासन और सतत औद्योगिक विकास** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नियमित संवाद, त्वरित निर्णय और समस्याओं के समयबद्ध समाधान की यह कार्यशैली निश्चित रूप से ग्रेटर नोएडा को राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेश मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाएगी। ■

ज्ञान क्रांति की नई पहल

जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम के नेतृत्व में जिला पुस्तकालय बनेगा आधुनिक नॉलेज हब



'जब प्रशासन की प्राथमिकता ज्ञान बन जाए, तब विकास की दिशा स्वतः बदलने लगती है।' गौतमबुद्धनगर में जिला पुस्तकालय को आधुनिक, सुलभ और जनोपयोगी ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम का प्रयास इसी सोच का सशक्त उदाहरण है।

जिला पुस्तकालय समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी **श्रीमती मेधा रूपम** ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, शोधार्थियों तथा आम नागरिकों के लिए **ज्ञान, नवाचार, शोध और बौद्धिक विकास का जीवंत केंद्र** होना चाहिए। यह दृष्टिकोण आज के बदलते शैक्षिक परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक और दूरदर्शी है।

उनके नेतृत्व में पुस्तकालय में नवीन एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों, समसामयिक पत्र-पत्रिकाओं और अध्ययन सामग्री की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को पुस्तकालय से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। यह पहल निश्चित रूप से जनपद में पढ़ने की संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

जिलाधिकारी ने पुस्तकालय भवन की आधारभूत सुविधाओं—कंप्यूटर, इंटरनेट, अध्ययन कक्ष, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और शांत वातावरण—को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश देकर यह संकेत दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण भी उतना ही आवश्यक है जितना बेहतर अध्ययन संसाधन।

विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने पुस्तकालय को केवल अध्ययन तक सीमित न रखकर **पुस्तक प्रदर्शनी, साहित्यिक गोष्ठी, पुस्तक चर्चा, करियर मार्गदर्शन, प्रेरक व्याख्यान तथा ज्ञानवर्धक गतिविधियों** का नियमित केंद्र बनाने पर भी जोर दिया। इससे पुस्तकालय सामाजिक संवाद, नवाचार और बौद्धिक विकास का मंच बन सकेगा।

आज जब युवा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, तब ऐसे दूरदर्शी प्रशासनिक प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका भविष्य में और भी अधिक बढ़ने वाली है। गौतमबुद्धनगर में जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम इस दिशा में एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में देखे जा सकते हैं।

जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम की यह पहल केवल पुस्तकालय के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं में अध्ययन संस्कृति, नवाचार, शोध और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव रखने का प्रयास है। यदि इस मॉडल को निरंतर आगे बढ़ाया गया, तो गौतमबुद्धनगर का जिला पुस्तकालय आने वाले समय में प्रदेश के उत्कृष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकता है।

युवा शक्ति से विकसित उत्तर प्रदेश की ओर

एकीकृत युवा नीति से खुलेगा अवसरों का नया क्षितिज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी पहल—कौशल, नवाचार, रोजगार, खेल और नेतृत्व के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सशक्त युवा भारत की मजबूत नींव

उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। ऐसे समय में जब भारत 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एकीकृत युवा नीति तैयार करने का निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं, प्रतिभा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का व्यापक विजन प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नीति का केंद्र बिंदु 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा होंगे। विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों तथा विभिन्न वर्गों के युवाओं से सीधे सुझाव लेकर नीति तैयार करना लोकतांत्रिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नीति वास्तविक जरूरतों और बदलती वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप बने।

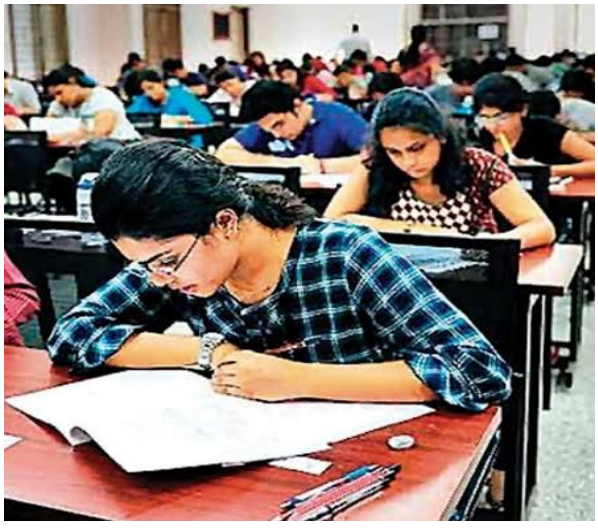
इस प्रस्तावित नीति की सबसे बड़ी विशेषता युवाओं के समग्र विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, खेल, डिजिटल सेवाएं और नेतृत्व विकास को एकीकृत कर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देकर उत्तर प्रदेश को नई अर्थव्यवस्था के लिए सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक दूरदर्शी पहल है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उद्यमिता और नवाचार का अनुकूल वातावरण विकसित करने, यूथ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने तथा स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के निर्देश यह दर्शाते हैं कि सरकार युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना चाहती है। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा को मजबूती मिलेगी।

युवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि छात्रवृत्ति, करियर मार्गदर्शन, रोजगार मिलान, प्रशिक्षण, सरकारी योजनाएं और अन्य सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध होंगी तो युवाओं का समय बचेगा,







पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं की पहुंच अधिक प्रभावी होगी।

'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। युवा आईएएस, आईपीएस अधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों की सहभागिता विद्यार्थियों को प्रेरणा, मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर प्रदान करेगी।

युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में आधुनिक पुस्तकालयों, अध्ययन केंद्रों एवं रीडिंग स्पेस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सुविधाओं का विस्तार ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहायक होगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा। खेलों को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक जनपद में खेल उत्कृष्टता केंद्र तथा प्रत्येक मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने की दिशा में सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे, फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाएंगे।

इसके साथ ही विशेषज्ञों की सहभागिता वाला स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित करने पर विचार युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की सतत निगरानी, मूल्यांकन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल सिद्ध हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की यह प्रस्तावित एकीकृत युवा नीति केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही दूरदर्शी विकास रणनीति है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह नीति प्रदेश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, नए अवसर और नई पहचान प्रदान करेगी। ■

युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उत्तर प्रदेश की एकीकृत युवा नीति का उद्देश्य युवाओं को केवल लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें विकास का भागीदार और नेतृत्वकर्ता बनाना है। कौशल, तकनीक, नवाचार, खेल, शिक्षा और उद्यमिता पर आधारित यह समग्र दृष्टिकोण निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को युवा सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही सशक्त युवा शक्ति विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की सबसे मजबूत आधारशिला बनेगी।





रेगिस्तान के हुनर को राष्ट्रीय पहचान

युवा बुनकर बरीगा राम ने रचा गौरव का नया अध्याय

परंपरा के धागों से उपलब्धि की कहानी

पट्टू साड़ी की विरासत को मिला राष्ट्रीय सम्मान

राजस्थान की मरुधरा केवल अपनी संस्कृति और रंगों के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं के लिए भी देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान रखती है। इसी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बाड़मेर जिले के युवा बुनकर **श्री बरीगा राम** ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। **12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस** के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में श्री बरीगा राम को **राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार-2025** से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति **श्रीमती द्रौपदी मुर्मु** ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया।

पट्टू साड़ी की बुनाई को मिला राष्ट्रीय मंच

बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र स्थित आलिसरो की बस्ती के निवासी बरीगा राम को **'पट्टू साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए युवा बुनकर'** श्रेणी में सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि परंपरागत हुनर यदि समर्पण, नवाचार और निरंतर अभ्यास से जुड़ जाए तो वह स्थानीय पहचान से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकता है। पट्टू साड़ी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की विशिष्ट बुनाई परंपरा का हिस्सा है। इसकी बुनाई में स्थानीय संस्कृति, रंग-बोध और पीढ़ियों से संजोया गया कौशल दिखाई देता है। बरीगा राम ने इसी विरासत को अपने हुनर के माध्यम से नई पहचान देने का कार्य किया है।

पिता से सीखा हुनर, मेहनत से बनाया मुकाम

बरीगा राम ने पट्टू साड़ी की पारंपरिक बुनाई की कला अपने पिता से सीखी। परिवार से मिली इस विरासत को उन्होंने केवल एक पेशे के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और जिम्मेदारी के रूप में अपनाया।

पारंपरिक बुनकर के रूप में निरंतर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी बुनाई कला में उत्कृष्टता हासिल की। राष्ट्रीय पुरस्कार उनके व्यक्तिगत कौशल का सम्मान होने के साथ-साथ उन अनगिनत ग्रामीण बुनकर परिवारों के योगदान की भी पहचान है, जो पीढ़ियों से भारतीय हस्तकरघा संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं।

युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश

आज जब युवा पीढ़ी आधुनिक रोजगार और नए व्यवसायों की ओर तेजी से बढ़ रही है, ऐसे समय में बरीगा राम की सफलता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है—**परंपरागत हुनर भी सम्मानजनक रोजगार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय पहचान का माध्यम बन सकता है।** उनका राष्ट्रीय सम्मान राजस्थान के ग्रामीण और पारंपरिक कारीगर समुदाय के युवाओं को अपनी विरासत से जुड़ने तथा उसे आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

हथकरघा: संस्कृति भी, रोजगार भी

हथकरघा भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ लाखों परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा पारंपरिक ज्ञान और कौशल का संरक्षण संभव होता है। बरीगा राम जैसे युवा बुनकरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना इस दिशा में सकारात्मक संकेत है। ऐसे सम्मान यह विश्वास मजबूत करते हैं कि **'वोकल फॉर लोकल', आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने की सोच** को जमीन पर उतारने में हथकरघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

विरासत से विकास की ओर

बरीगा राम की कहानी केवल एक पुरस्कार की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां गांवों और छोटे कस्बों में पीढ़ियों से संजोए गए हुनर आज राष्ट्रीय मंच पर सम्मान पा रहे हैं। राजस्थान की पट्टू साड़ी के धागों में बुनी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि **अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।** राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार ने बरीगा राम के हुनर को सम्मान दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि उनके माध्यम से **राजस्थान की पारंपरिक बुनाई और ग्रामीण कारीगरों की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान मिली है।** ■

मजदूरी से उद्यमिता तक: निर्मला ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

आजीविका मिशन का सहारा, हुनर की उड़ान और सालाना ढाई लाख की कमाई—सोनभद्र की ग्रामीण महिला बनीं प्रेरणा





कभी परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी करने वाली सोनभद्र की निर्मला आज अपने हुनर और हौसले के दम पर सफल उद्यमी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिले प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज रंग-बिरंगी डिजाइनर मोमबत्तियों से लेकर जूस, पॉपकॉर्न, गुलकंद, शर्बत और गाजर के मुरब्बे तक का कारोबार कर रहीं निर्मला की सालाना आय करीब **ढाई लाख रुपये** तक पहुंच गई है।

सोनभद्र के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के बिचपई गांव की निर्मला बीए तक शिक्षित हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और घर की जिम्मेदारियों के साथ उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती थी। बेहतर भविष्य की तलाश में उन्होंने स्वयं सहायता समूह का दामन थामा। यहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई।

60 हजार की सीड मनी ने दिया कारोबार को आधार

निर्मला ने मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण लेकर अपने हुनर को रोजगार में बदलने का फैसला किया। उद्यमिता विकास परियोजना के तहत उन्हें **60 हजार रुपये की सीड मनी** मिली। इस सहायता से उन्होंने विभिन्न डिजाइनों के मोमबत्ती सांचे खरीदे और त्योहारों के अवसर पर आकर्षक मोमबत्तियों का उत्पादन शुरू किया। मांग बढ़ी तो शौक धीरे-धीरे नियमित कारोबार में बदल गया।

इसके बाद खादी ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से उन्हें पॉपकॉर्न मशीन मिली। खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने गुलाब का गुलकंद, शर्बत और गाजर का मुरब्बा बनाना भी सीख लिया। अब वह मौसम और बाजार की मांग के अनुसार अलग-अलग उत्पाद तैयार करती हैं।

एक महिला की सफलता, गांव की कई महिलाओं की प्रेरणा

निर्मला की उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं के लिए भी आत्मविश्वास की मिसाल बन गई है। उनके उद्यम से प्रेरित होकर **12 से 15 महिलाएं** रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

निर्मला के लिए यह बदलाव आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। जो महिला कभी लोगों से बात करने में झिझकती थीं, आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उत्पाद और कारोबार की चर्चा करती हैं। बढ़ी हुई आमदनी से बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी हो रही हैं।

हुनर, सहयोग और संकल्प से बदली तस्वीर

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल से स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और बाजार से जोड़ने का माध्यम बन रहे हैं। निर्मला की कहानी बताती है कि **जब हुनर को अवसर और मेहनत को सरकारी सहयोग मिलता है, तो गांव की महिला केवल रोजगार पाने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी भी बन सकती है।** ■

निर्मला की यात्रा एक संदेश है—मजबूरी से शुरू हुआ सफर, आत्मनिर्भरता की मंजिल तक पहुंच सकता है।

मिंजर की सुनहरी डोर में सजा हिमाचल का गौरव

परंपरा, संस्कृति और जनभागीदारी का अद्भुत संगम बना अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला



आयोजन: अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026
स्थान: चंबा, हिमाचल प्रदेश
अवधि: 26 जुलाई–2 अगस्त 2026
मुख्य आकर्षण: पारंपरिक शोभायात्रा, स्थानीय देवी-देवताओं की भागीदारी, लोक संस्कृति और मिंजर विसर्जन
समापन संदेश: परंपरा से जुड़कर विकास की नई राह—यही हिमाचल की असली पहचान है।

हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल उसकी बर्फीली चोटियों, हरी-भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से भी है। **चंबा का अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला** इसी जीवंत विरासत का ऐसा उत्सव है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आधुनिक हिमाचल की नई ऊर्जा के साथ कदमताल करती दिखाई देती हैं।

26 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित सप्ताहव्यापी अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन भी उसी भव्यता और पारंपरिक रंग में हुआ, जिससे इसकी सांस्कृतिक गरिमा और अधिक निखर उठी।

जब परंपरा बनी जन-आस्था का उत्सव

समापन अवसर पर मुख्यमंत्री **ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू** ने अखंड चंडी पैलेस से मंजरी गार्डन तक निकलने वाली पारंपरिक शोभायात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप मिंजर—अर्थात सुनहरी तस्सल—का रावी नदी में विसर्जन किया गया। नारियल, मौसमी फलों और लाल कपड़े में लिपटे सिक्के के साथ मिंजर अर्पित करते हुए प्रदेश की शांति, समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। यह दृश्य केवल एक धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि **हिमाचल की सामूहिक चेतना, लोकविश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक** बनकर सामने आया।

लोकसंस्कृति की जीवंत तस्वीर

शोभायात्रा में स्थानीय देवी-देवताओं की भागीदारी, पारंपरिक परिधानों में सजे महिला-पुरुष, लोक कलाकार, पर्यटक, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज तथा हिमाचल पुलिस और होमगार्ड के दलों ने चंबा की सांस्कृतिक छटा को जीवंत कर दिया। मिंजर मेले की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां **अतीत केवल स्मृति बनकर नहीं रहता, बल्कि वर्तमान के साथ उत्सव के रूप में आगे बढ़ता है।**

संस्कृति से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक

ऐसे आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने के साथ पर्यटन को भी गति प्रदान करते हैं। स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पकारों, छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मेले जैसे आयोजन आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण अवसर बनते हैं।

इस दृष्टि से मिंजर मेला **संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय उत्पाद और जनभागीदारी को एक मंच पर जोड़ने वाला उत्सव** भी है। हिमाचल की लोकसंस्कृति उसकी अमूल्य पूंजी है। इसे संरक्षित करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, युवा पीढ़ी, कलाकारों और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। चंबा की धरती पर रावी के प्रवाह में विसर्जित होती मिंजर मानो यही संदेश देती है कि **परंपराएं तब तक जीवित रहती हैं, जब तक उन्हें नई पीढ़ियां सम्मान के साथ आगे बढ़ाती रहती हैं।** ■

मिंजर की यह परंपरा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है—विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही वास्तविक समृद्धि है।

गोबर से गोल्ड तक

GOBARdhan योजना से आत्मनिर्भर भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति



GOBARdhan केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत की विकास सोच में हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। जब खेतों का अवशेष, पशुधन का गोबर और जैविक कचरा ऊर्जा, रोजगार और आय का माध्यम बनता है, तब विकास का वास्तविक लाभ गांवों तक पहुँचता है। स्वच्छ ऊर्जा, समृद्ध किसान और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था— यही नए भारत की पहचान बन रही है।

भारत आज ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना – GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan)** को स्वीकृति देना देश की हरित विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह योजना कृषि अवशेष, पशुधन से प्राप्त गोबर, चीनी मिलों के प्रेसमड, नगरों के जैविक कचरे तथा अन्य बायोमास संसाधनों को उपयोगी ऊर्जा एवं आर्थिक संपदा में परिवर्तित करने की व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य केवल स्वच्छ ईंधन तैयार करना नहीं, बल्कि 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को व्यवहार में उतारते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देना भी है।

कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से समृद्धि

भारत में प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कृषि एवं जैविक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। अब यही अपशिष्ट बायोगैस, कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG), जैविक खाद तथा अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में उपयोग होगा। इससे खेतों में पराली जलाने की समस्या कम होगी, स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय के नए स्रोत विकसित होंगे।

ग्रामीण भारत के लिए नए अवसर

GOBARdhan योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बायोएनर्जी संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और गांव ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेंगे। किसान अब कृषि अवशेष और गोबर को अनुपयोगी नहीं, बल्कि अतिरिक्त आय के साधन के रूप में देख सकेंगे।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल

यह योजना कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने तथा कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक एवं टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, जिससे मिट्टी की उर्वरता और कृषि की गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

विकसित भारत की मजबूत नींव

राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ भारत, जलवायु संरक्षण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को गति प्रदान करेगी। यह पहल प्रधानमंत्री के **'वेस्ट टू वेल्थ', हरित विकास, सतत विकास तथा विकसित भारत 2047** के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। ■

'कचरे से संपदा, ऊर्जा से समृद्धि और नवाचार से विकसित भारत' — GOBARdhan योजना इसी परिवर्तनकारी सोच का सशक्त उदाहरण है।

सशक्त नारी, समृद्ध उत्तराखंड की नई तस्वीर

मातृशक्ति बनी विकास की धुरी, आत्मनिर्भरता से नेतृत्व तक बढ़ते कदम



उत्तराखंड की विकास यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका हमेशा से विशिष्ट रही है। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच परिवार, खेती-बागवानी, पशुपालन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को संभालने वाली उत्तराखंड की महिलाएं अब पारंपरिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर **उद्यमिता, स्वरोजगार, कौशल विकास, तकनीक और नेतृत्व** के नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। तीज उत्सव के अवसर पर देहरादून के भाऊवाला में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उनके विचारों, सुझावों और अपेक्षाओं को सुना। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने महिला शक्ति को उत्तराखंड के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला बताया।

सम्मान से नेतृत्व तक— बदल रही है तस्वीर

मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि महिलाओं को **अवसर, संसाधन, बाजार, सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति** से जोड़ना आवश्यक है। आज उत्तराखंड की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, खाद्य

प्रसंस्करण, होमस्टे, पर्यटन और छोटे उद्यमों में उनकी भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है। इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर आय के नए स्रोत विकसित हो रहे हैं।

लखपति दीदी से उद्यमी दीदी तक

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरे हैं। प्रदेश में **2.65 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी'** बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। यह आंकड़ा केवल आर्थिक सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं में बढ़ते आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है।

सरकार द्वारा स्वरोजगार, आजीविका और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के पारंपरिक विकल्पों से आगे बढ़ाकर उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

तकनीक से जुड़ रही पहाड़ की नारी

उत्तराखंड की महिला शक्ति अब तकनीक को भी अपनी आर्थिक प्रगति का माध्यम बना रही है। **'ड्रोन दीदी', 'सोलर सखी' और 'महिला सारथी'** जैसी पहलें महिलाओं को आधुनिक तकनीक और नए रोजगार अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

विशेष रूप से सौर ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और ड्रोन आधारित सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भविष्य के अनुरूप तैयार करने की क्षमता रखती है।

स्थानीय उत्पादों को बाजार, महिलाओं को नई पहचान



महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए **'हाउस ऑफ हिमालयाज'** जैसे मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को ब्रांड, पैकेजिंग और बाजार से जोड़कर महिलाओं की मेहनत को बेहतर आर्थिक मूल्य दिलाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद यदि आधुनिक बाजार, ई-कॉमर्स और पर्यटन से प्रभावी रूप से जुड़ते हैं, तो यह महिला उद्यमिता के साथ-साथ 'लोकल से ग्लोबल' की अवधारणा को भी मजबूत कर सकता है।

समान अवसर और निर्णय की शक्ति

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ तब पूरा होता है जब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी न होकर **निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व में सक्रिय भागीदार बनें।**

सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे प्रावधान महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल और आर्थिक आत्मनिर्भरता—इन सभी क्षेत्रों में समान अवसर महिलाओं को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाते हैं।



'सशक्त नारी-समृद्ध उत्तराखंड' का संकल्प

उत्तराखंड की मातृशक्ति ने राज्य निर्माण के संघर्ष से लेकर वर्तमान विकास यात्रा तक अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता साबित की है। आज आवश्यकता इस शक्ति को आधुनिक अवसरों से जोड़ने की है। यदि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बाजार, युवतियों को कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण, महिला उद्यमियों को आसान वित्तीय सहायता और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो उत्तराखंड की महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था की नई growth engine बन सकती हैं।

सशक्त महिला केवल अपने परिवार को मजबूत नहीं करती, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। उत्तराखंड के संदर्भ में यह बदलाव केवल महिला सशक्तिकरण की कहानी नहीं, बल्कि **आत्मनिर्भर गांव, मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था और समृद्ध उत्तराखंड की नई विकास गाथा है।**

- **मातृशक्ति को अवसर दीजिए, वह विकास को गति देगी।**
- **महिला को बाजार से जोड़िए, वह गांव की अर्थव्यवस्था बदल देगी।**
- **महिला को नेतृत्व दीजिए, वह उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा देगी।**
- **यही भावना 'सशक्त नारी—समृद्ध उत्तराखंड' के संकल्प को वास्तविक जनआंदोलन में बदल सकती है।** ■

जापान का भरोसा, यूपी की उड़ान

तकनीक जापान की, ताकत उत्तर प्रदेश की— साथ मिलकर खुल रहे विकास के नए दरवाजे

निवेश से उद्योग | उद्योग से रोजगार | तकनीक से कौशल | संस्कृति से रिश्ते | साझेदारी से विकास

यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 ने खोले सहयोग के नए द्वार। यीडा की जापान सिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और एमएसएमई तक बढ़ा साझेदारी का दायरा

उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्ते अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। **यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026** ने निवेश और उद्योग से आगे बढ़कर तकनीक, कौशल, रोजगार, शिक्षा, कृषि, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के कई नए रास्ते खोले हैं।



एक नजर में यूपी-जापान साझेदारी

- 3,191 करोड़ — एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की प्रस्तावित परियोजनाओं का कुल निवेश
- 10 हजार+ — संभावित रोजगार अवसर
- 500 एकड़ — यीडा में प्रस्तावित जापान सिटी
- 200+ — जापानी उद्योगपति, सीईओ और प्रतिनिधि
- ग्रीन हाइड्रोजन — स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग की नई संभावना
- गलगोटियास यूनिवर्सिटी — शिक्षा, स्किलिंग और रिसर्च का नया भारत-जापान सेतु
- बौद्ध सर्किट — जापान से उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक पर्यटन को जोड़ने की संभावना



18 से 23 अगस्त तक आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जापान के **200 से अधिक सीईओ, उद्योगपति, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति-निर्माता** उत्तर प्रदेश पहुंचे। यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर **कोटारो नागासाकी** के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल की व्यापक भागीदारी ने प्रदेश के प्रति जापानी उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को सामने रखा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए विभिन्न संवादों में निवेश के साथ-साथ तकनीक और रोजगार को जोड़ने पर विशेष जोर रहा। संदेश स्पष्ट था—उत्तर प्रदेश जापान से केवल पूंजी नहीं चाहता, बल्कि **तकनीक, गुणवत्ता, कौशल और वैश्विक अनुभव के साथ दीर्घकालिक साझेदारी** चाहता है।

यीडा में जापान की बड़ी दस्तक

निवेश के साथ बनेगा रोजगार और सप्लाई चेन का नया इकोसिस्टम

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में **यीडा** तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निवेश सम्मेलन के दौरान **एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन** की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग ने इस क्षेत्र की संभावनाओं





को और मजबूत किया।

दोनों परियोजनाओं में करीब **3,191 करोड़ के प्रस्तावित निवेश** और 10 हजार से अधिक रोजगार अवसरों की संभावना है। यह निवेश केवल दो औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं रहेगा। इनके आसपास सप्लायर, एंसिलरी यूनिट, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, सर्विस और अन्य छोटे उद्योगों के लिए भी अवसर बनेंगे। यही किसी बड़े औद्योगिक निवेश की वास्तविक ताकत होती है— **एक कंपनी आती है और उसके साथ पूरा कारोबारी नेटवर्क विकसित होता है।**

नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता और जेवर में विकसित हो रही कनेक्टिविटी यीडा को भविष्य के विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत आधार दे रही है।

500 एकड़ की जापान सिटी

जापानी कंपनियों के लिए यूपी में नया कारोबारी ठिकाना

यीडा क्षेत्र में प्रस्तावित **500 एकड़ की जापान सिटी** इस साझेदारी की दीर्घकालिक तस्वीर पेश करती है। जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर और एंसिलरी उद्योगों को एक ही औद्योगिक इकोसिस्टम में जोड़ने की सोच से उत्पादन, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिल सकती है। इसके साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यदि जापान सिटी अपेक्षित रूप से विकसित होती है, तो उत्तर प्रदेश जापानी कंपनियों के लिए केवल बाजार नहीं, बल्कि **उत्पादन और निर्यात का महत्वपूर्ण आधार** बन सकता है।

जापान सिटी—निवेश से आगे, एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम।

जापान की प्रिसिजन, यूपी का स्केल

दो ताकतों का संगम बदल सकता है औद्योगिक तस्वीर

जापान विश्वभर में अपनी **गुणवत्ता, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, अनुशासन और तकनीकी दक्षता** के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, कृषि क्षमता और तेजी से विकसित होता औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों की खूबियों का मेल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटेरियल और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री **अश्विनी वैष्णव** ने भारत की आर्थिक प्रगति में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की भूमिका को रेखांकित किया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री **सुरेश खन्ना** ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी, बाजार और मानव संसाधन को प्रदेश की प्रमुख ताकत बताया।

तकनीक जापान की, बाजार और युवा शक्ति यूपी की — साझेदारी का यही सबसे बड़ा आधार है।

निवेश से आगे—अब आरएंडडी की बारी

भविष्य की औद्योगिक ताकत प्रतिभा और तकनीक से बनेगी

आज के दौर में सिर्फ बड़े निवेश से औद्योगिक





प्रतिस्पर्धा तय नहीं होती। **रिसर्च, इनोवेशन, तकनीकी प्रतिभा और इंडस्ट्री-रेडी स्किल** भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

यूपी-जापान संवाद में आरएंडडी और स्किलिंग की संभावनाओं पर चर्चा इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है।

जापानी कंपनियों की प्रिसिजन इंजीनियरिंग और उत्तर प्रदेश की युवा प्रतिभा को जोड़कर रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट साझेदारी और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है।

गलगोटियास यूनिवर्सिटी बना टैलेंट ब्रिज

क्लासरूम से ग्लोबल करियर तक बढ़ेगी साझेदारी

ग्रेटर नोएडा स्थित **गलगोटियास यूनिवर्सिटी** में यामानाशी के 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा भारत-जापान रिश्तों के शैक्षणिक पक्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा।

इस अवसर पर **यामानाशी प्रीफेक्चर गवर्नमेंट के साथ एमओयू और यामानाशी यूनिवर्सिटी के साथ LOI** किया गया।

छात्र विनिमय, फैकल्टी सहयोग, तकनीकी प्रशिक्षण और संयुक्त अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में इससे नए अवसर बनने की उम्मीद है।

विश्वविद्यालय की एआई, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और आधुनिक तकनीक से जुड़ी प्रयोगशालाओं का प्रतिनिधिमंडल ने अवलोकन किया।

गलगोटियास यूनिवर्सिटी के सीईओ **डॉ. ध्रुव गलगोटिया** ने वैश्विक करियर और रिसर्च सहयोग पर जोर दिया, जबकि कुलाधिपति **सुनील गलगोटिया** ने भारत-जापान संबंधों को ज्ञान और पारस्परिक सम्मान की साझेदारी बताया।

यामानाशी के गवर्नर **कोटारो नागासाकी** की विश्वविद्यालय की सराहना और यह टिप्पणी कि 30 वर्ष पहले ऐसा अवसर मिलता तो वे यहां प्रवेश लेना पसंद करते, कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही।

नई शिक्षा का नया मंत्र—डिग्री के साथ दुनिया को समझना।

युवा शक्ति को जापान से जोड़ने की तैयारी

जापानी भाषा और तकनीकी कौशल बनेंगे रोजगार की कुंजी

जापान के साथ बढ़ते औद्योगिक संबंधों का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिल सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग, नर्सिंग, केयरगिविंग, लॉजिस्टिक्स, कृषि और सेवा क्षेत्र में जापानी भाषा और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि स्किलिंग को उद्योग की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए।

इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल और स्किल के अनुसार रोजगार।

यह मॉडल उत्तर प्रदेश की युवा आबादी को स्थानीय से वैश्विक रोजगार बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन से स्वच्छ भविष्य

यामानाशी की तकनीक और यूपी की औद्योगिक क्षमता का नया मेल

ग्रीन हाइड्रोजन यूपी-जापान साझेदारी का सबसे भविष्यवादी क्षेत्र बनकर उभरा है।

यामानाशी की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक जरूरतों के बीच तालमेल से उत्पादन, स्टोरेज, रिसर्च और औद्योगिक उपयोग में नई परियोजनाओं की संभावनाएं बन सकती हैं।

आईआईटी कानपुर और आईआईटी-बीएचयू जैसे संस्थानों की शोध क्षमता इस क्षेत्र को मजबूत तकनीकी आधार दे सकती है।

ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा नहीं—नई तकनीक और रोजगार का भी नया क्षेत्र है।

किसान के खेत तक जापानी तकनीक

स्मार्ट एग्रीकल्चर से गांवों में नए अवसर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री **शिवराज सिंह चौहान** ने जापानी तकनीक को छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कम पानी में बेहतर उत्पादन, आधुनिक कृषि









मशीनरी, लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि के लिए जापान का अनुभव उपयोगी हो सकता है।

कृषि मशीनरी के संचालन और रखरखाव के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने से गांवों में सर्विस सेंटर और नए स्वरोजगार मॉडल भी विकसित किए जा सकते हैं।

तकनीक खेत तक पहुंचेगी, तो रोजगार गांव तक पहुंचेगा।

ताजमहल से बौद्ध सर्किट तक

पर्यटन बनेगा भारत-जापान दोस्ती का सांस्कृतिक सेतु

आगरा, लखनऊ और काशी की यात्राओं ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश की



सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया।

ताजमहल, ब्रज की संस्कृति, लखनऊ की अवधी तहजीब, गंगा आरती और काशी की आध्यात्मिक विरासत जापानी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बन सकती है।

भगवान बुद्ध से जुड़ी साझा विरासत इस सहयोग को और मजबूत आधार देती है।

सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे स्थलों को जापानी पर्यटन बाजार से जोड़ने के लिए विशेष बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की संभावनाएं हैं।

जापानी भाषा में सुविधाएं, डिजिटल प्रचार, बेहतर आतिथ्य और विशेष पैकेज इस दिशा में



महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

बुद्ध की धरती से जापान तक— पर्यटन के रास्ते दोस्ती और रोजगार दोनों बढ़ सकते हैं।

काशी की संस्कृति से कारीगरों तक

ओडीओपी और जीआई उत्पादों को मिल सकता है नया बाजार

बनारसी सिल्क, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने और अन्य पारंपरिक उत्पाद उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान हैं।

जापानी पर्यटकों और खरीदारों के बीच इन उत्पादों को बढ़ावा देने से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकता है।





पर्यटन का एक नया अर्थ— घूमने वाला पर्यटक, स्थानीय अर्थव्यवस्था का भागीदार।

एमएसएमई को मिलेगा जापानी अनुभव

बड़ी कंपनियों के साथ छोटे उद्योगों के लिए भी नए अवसर

उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को जापानी कंपनियों की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। जापानी गुणवत्ता मानकों, तकनीक, उत्पादन प्रबंधन और वैश्विक सप्लाई चेन का अनुभव स्थानीय उद्योगों की क्षमता बढ़ा सकता है। **स्पार्क मिंडा, मदरसन, लोहम और डेन्सो** जैसे समूहों की प्रदेश में मौजूदगी इस औद्योगिक साझेदारी को मजबूत आधार देती है।

जापानी कंपनियां आएं और यूपी के छोटे उद्योग उनके साथ आगे बढ़ें—यही साझेदारी का व्यापक लाभ होगा।

जब विद्यार्थियों ने जोड़ी दोस्ती

'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' ने रिश्तों में भरा नया रंग

यामानाशी और लखनऊ के विद्यार्थियों के बीच संवाद ने पूरे आयोजन को विशेष मानवीय स्पर्श दिया।

जापानी विद्यार्थियों के गीत, भारतीय



विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओरिगेमी के माध्यम से शांति एवं मित्रता का संदेश दो संस्कृतियों के बीच सहज जुड़ाव का प्रतीक बना।

सरकारें समझौते करती हैं, उद्योग निवेश करते हैं, लेकिन दोस्ती को स्थायी नई पीढ़ी बनाती है।

महिला सुरक्षा में भी साझा अनुभव

1090 मॉडल से जापानी प्रतिनिधियों का संवाद

जापानी महिला प्रतिनिधियों का **वीमेन पावर लाइन 1090** का दौरा सामाजिक सहयोग की दिशा में उल्लेखनीय पहल रहा।

महिला सुरक्षा, काउंसलिंग, शिकायत निवारण और जागरूकता के मॉडल को समझने के साथ दोनों पक्षों ने अनुभव साझा किए।

यह सहयोग दिखाता है कि भारत-जापान रिश्ते आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ **सामाजिक विकास और मानव कल्याण** से भी जुड़े हैं।



विधानसभा से प्रीफेक्चर तक
साझेदारी को मिला संस्थागत आधार

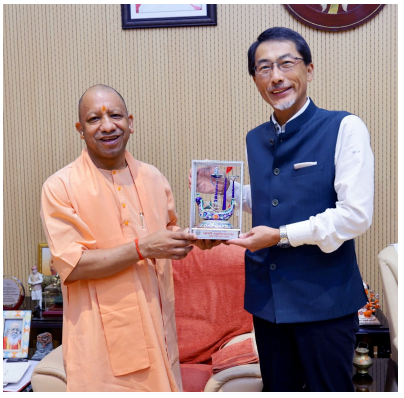
उत्तर प्रदेश विधानसभा और यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली के बीच समझौते से सहयोग को नया संस्थागत आयाम मिला है।

शिक्षा, कृषि, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान और अनुभव साझा करने से दोनों पक्षों के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं।

यह राज्य और प्रीफेक्चर स्तर पर भारत-जापान सहयोग का एक उपयोगी मॉडल बन सकता है।

एमओयू से जमीन तक
अब समझौतों को परिणाम में बदलने की चुनौती

यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट ने कई बड़े अवसर सामने रखे हैं। अब अगला चरण इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है।



सफलता तभी मानी जाएगी

जब—

निवेश जमीन पर उतरे,
उद्योग स्थापित हों,
युवाओं को कौशल मिले,
रोजगार बढ़े,
एमएसएमई जुड़ें,
किसानों तक तकनीक पहुंचे,
पर्यटन को नया बाजार मिले
और निर्यात की क्षमता मजबूत हो।



निवेश से बड़ी है विश्वास की साझेदारी

यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 का सबसे सकारात्मक संदेश यही है कि यह साझेदारी केवल पूंजी की नहीं है।

यह—

तकनीक को प्रतिभा से,
प्रतिभा को कौशल से,
कौशल को रोजगार से,
कृषि को तकनीक से,
पर्यटन को संस्कृति से
और निवेश को विश्वास से
जोड़ने की पहल है।
जापान के पास तकनीक,
गुणवत्ता और वैश्विक
औद्योगिक अनुभव है। उत्तर
प्रदेश के पास युवा शक्ति,
विशाल बाजार, कृषि एवं
औद्योगिक क्षमता और तेजी
से विकसित होता
इंफ्रास्ट्रक्चर है।
यदि दोनों की ताकतें सही
तरीके से जुड़ती हैं, तो इसका
लाभ केवल बड़ी कंपनियों
को नहीं, बल्कि युवा,
किसान, एमएसएमई,
कारीगर, स्टार्टअप और
स्थानीय उद्यमियों तक पहुंच
सकता है।
यही इस साझेदारी की असली
सफलता होगी।

प्रस्तावित **यामानाशी डेस्क** जैसे संस्थागत प्रयास निवेशकों और सरकार के बीच लगातार संवाद और समन्वय को मजबूत कर सकते हैं। ■







मिट्टी से मुकाम तक

ओडीओपी ने तराशा हुनर, टेराकोटा ने राजन प्रजापति को दी नई पहचान

उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कला और शिल्प अब केवल विरासत नहीं, बल्कि रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित **'एक जनपद एक उत्पाद' (ओडीओपी)** योजना ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बाजार, तकनीक और नई पहचान से जोड़ने का काम किया है। गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकार **राजन प्रजापति** की सफलता इसी बदलाव की प्रेरक कहानी है।

कभी सीमित संसाधनों और पारंपरिक तरीकों के बीच काम करने वाले राजन आज लगभग **डेढ़ करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार** करने वाले सफल उद्यमी हैं। उनकी इकाई में 25 से अधिक कारीगरों को नियमित रोजगार मिल रहा है। यानी मिट्टी से बने उत्पादों ने न केवल उनकी अपनी जिंदगी बदली, बल्कि कई परिवारों के लिए आय और सम्मान का रास्ता भी खोला है।



पुश्तैनी हुनर को बनाया आधुनिक कारोबार

गोरखपुर के औरंगाबाद, लंगड़ी गुलरिहा गांव के निवासी राजन प्रजापति ने अपने पुश्तैनी टेराकोटा शिल्प को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप ढाला। उनका मानना है कि परंपरा तभी जीवित रह सकती है, जब वह बदलते समय के साथ कदम मिलाए।

इसी सोच के साथ उन्होंने पारंपरिक तकनीकों के साथ आधुनिक उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया। इलेक्ट्रिक चाक और आधुनिक तकनीक ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन में भी सुधार किया। परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाला टेराकोटा अब देश के विभिन्न बड़े शहरों तक पहुंचने लगा।

ओडीओपी बना बदलाव का मजबूत आधार

राजन की सफलता में ओडीओपी योजना

की महत्वपूर्ण भूमिका रही। योजना के माध्यम से उन्हें आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से जुड़ने के अवसर मिले। इससे पारंपरिक शिल्प को कारोबारी दृष्टिकोण मिला और उत्पादन को बड़े बाजार की जरूरत के अनुरूप विस्तार देने में मदद मिली।

यह बदलाव बताता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव तब और व्यापक हो जाता है, जब **नीति, तकनीक और स्थानीय हुनर** एक साथ जुड़ते हैं।

जीआई टैग ने टेराकोटा को दिलाई नई पहचान

गोरखपुर के टेराकोटा शिल्प को जीआई टैग मिलने से इस पारंपरिक कला की विशिष्ट पहचान और मजबूत हुई। इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार में प्रस्तुत करने का विश्वास मिला।

आज मांग बढ़ने के साथ त्योहारों और विशेष अवसरों पर राजन की इकाई से बड़ी मात्रा में टेराकोटा उत्पाद दूसरे राज्यों को भेजे जाते हैं। यह स्थानीय शिल्प के बढ़ते बाजार और बदलती उपभोक्ता पसंद का संकेत है।

एक उद्यमी से बने रोजगारदाता

राजन प्रजापति की कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उनका कारोबार नहीं, बल्कि **रोजगार सृजन** है। 25 से अधिक कारीगरों को नियमित काम देकर उन्होंने यह साबित किया है कि एक स्थानीय शिल्पकार भी सफल उद्यमी बनकर अपने आसपास आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है।

उनकी कार्यशाला अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं रही, बल्कि प्रशिक्षण का माध्यम भी बन चुकी है। यहां युवाओं को टेराकोटा निर्माण की बारीकियां सिखाई जाती हैं। इससे पारंपरिक कला अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है और युवा इसे रोजगार तथा स्वरोजगार के विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

परंपरा से आधुनिक बाजार तक का सफर

राजन प्रजापति की सफलता यह संदेश देती है कि भारत की पारंपरिक कलाओं में बाजार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है उन्हें **आधुनिक डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग** से जोड़ने की।

टेराकोटा जैसे पर्यावरण-अनुकूल और हस्तनिर्मित उत्पाद आज उन उपभोक्ताओं के बीच भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो स्थानीय, प्राकृतिक और पारंपरिक उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में गोरखपुर का टेराकोटा आने वाले समय में घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी और मजबूत जगह बना सकता है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की जीवंत तस्वीर

ओडीओपी की मूल भावना स्थानीय क्षमता को स्थानीय स्तर पर मजबूत करते हुए उसे बड़े बाजार तक पहुंचाने की है। राजन प्रजापति इसी सोच के जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी पारंपरिक विरासत को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उसे **ब्रांड, व्यवसाय और रोजगार के अवसर** में बदल दिया।

उनकी यात्रा यह बताती है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में मौजूद हुनर यदि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ जाए, तो वह बड़े आर्थिक बदलाव का आधार बन सकता है।

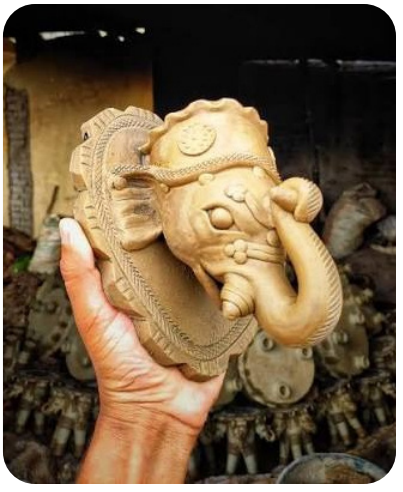
मिट्टी में छिपी है तरक्की की ताकत

राजन प्रजापति की कहानी केवल एक कारीगर के सफल उद्यमी बनने की कहानी नहीं है। यह उस बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां **स्थानीय हुनर को सम्मान, तकनीक को अवसर और उद्यमिता को प्रोत्साहन** मिल रहा है।

गोरखपुर की मिट्टी से निकली टेराकोटा कला आज रोजगार और पहचान दोनों दे रही है। राजन जैसे उद्यमी यह साबित कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहीं दूर से नहीं, बल्कि **अपने गांव, अपनी कला और अपने हुनर** से की जा सकती है। ■







स्थानीय उत्पाद से वैश्विक पहचान तक का यह सफर उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है।



परंपरा को पहचान, हुनर को सम्मान

हिमाचल की हस्तशिल्प विरासत को मिला वैश्विक पहचान का नया आधार

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सदियों से संजोई गई लोककला और हस्तशिल्प की परंपरा अब अपनी स्थानीय पहचान से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश के **रणसिंघा, लकड़ी की नक्काशी और हस्तनिर्मित कालीन** जैसे पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में **Geographical Indication (GI)** टैग मिलना हिमाचल के कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

GI टैग—कारीगर के हुनर की आधिकारिक पहचान

GI टैग केवल किसी उत्पाद के नाम के साथ जुड़ा प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि उस उत्पाद की **विशिष्टता, प्रामाणिकता और भौगोलिक पहचान की सुरक्षा** का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे हिमाचली उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में अलग पहचान मिलने की संभावना बढ़ेगी तथा उनसे जुड़े कारीगरों और समुदायों को अपने हुनर का बेहतर आर्थिक मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

इस उपलब्धि में **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय** की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थानीय उत्पादक एवं कारीगर समूहों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से GI पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

राजभवन में हुनर को मिला सम्मान

लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल **कविंदर गुप्ता** ने GI प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इनमें कुल्लू की **आचरी फाउंडेशन** से जुड़े मनीष भारती और महेश भारती, कालीन कारीगर शंकुतला देवी, मंडी की SAVM संस्था से जुड़ी हीरा मणि, रणसिंघा कारीगर प्रदीप कुमार तथा लकड़ी की नक्काशी के कारीगर कृष्ण लाल शामिल रहे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर पारंपरिक उत्पादों की पहचान को मजबूत करने के साथ-साथ **गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, आधुनिक मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और व्यापक बाजार संपर्क** पर विशेष जोर दिया। उद्देश्य स्पष्ट है—हिमाचल की कला को केवल पर्यटकों तक सीमित न रखकर देश और दुनिया के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना।

जब विरासत बने रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम

हिमाचली हस्तशिल्प की सबसे बड़ी ताकत उसकी मौलिकता है। स्थानीय कारीगर प्रकृति, संस्कृति और पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल को अपने उत्पादों में उतारते हैं। ऐसे में GI पहचान इस परंपरा को **संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक अवसर** से जोड़ने का रास्ता खोलती है।

यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका के अवसरों को मजबूत करने और पारंपरिक कारीगर समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक हो सकती है।

> 'जिस हाथ ने पीढ़ियों तक हिमाचल की संस्कृति को आकार दिया, अब वही हाथ वैश्विक बाजार में अपनी पहचान गढ़ने की ओर बढ़ रहा है।'

परंपरा से आधुनिक बाजार तक—नई पीढ़ी के लिए नई राह

आज आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक हुनर को केवल विरासत के रूप में संरक्षित न किया जाए, बल्कि उसे **आधुनिक डिजाइन, बेहतर पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स** से जोड़ा जाए। इससे युवा पीढ़ी भी पारंपरिक शिल्प को रोजगार और उद्यमिता के आकर्षक विकल्प के रूप में अपना सकती है।

राज्यपाल ने भी पारंपरिक कौशल को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और हस्तशिल्प को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर जोर दिया है।

GI टैग के माध्यम से हिमाचल की पारंपरिक कला को संरक्षण, सम्मान और बाजार—तीनों का नया आधार मिल रहा है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि **विरासत को बचाकर भी विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है।**

रणसिंघा की गूंज, लकड़ी की नक्काशी की बारीकी और हाथ से बुने कालीनों की खूबसूरती—अब हिमाचल की पहचान से आगे बढ़कर वैश्विक बाजार में दस्तक देने को तैयार है। ■

बिहार की नई औद्योगिक उड़ान

- **फुटवियर और लेदर सेक्टर में 125 करोड़ का निवेश, 1,800 रोजगार की नई संभावनाएं**
- **IIFF 2026 में बिहार ने दिखाई औद्योगिक क्षमता, निवेशकों के लिए खुला नया द्वार**



बिहार अब केवल कृषि और पारंपरिक उद्योगों की पहचान तक सीमित नहीं है। राज्य तेजी से अपने औद्योगिक परिदृश्य को विस्तार दे रहा है और नई विनिर्माण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। **10वें इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर (IIFF) 2026** में बिहार ने फुटवियर एवं लेदर उद्योग के क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को जिस प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, वह राज्य की बदलती औद्योगिक तस्वीर का संकेत है। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित **"Bihar: The Next Frontier of Global Footwear Manufacturing"** विषयक राज्य सत्र में बिहार को देश के उभरते फुटवियर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार, उद्योग जगत, निवेशकों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में बिहार की औद्योगिक नीतियों, भूमि उपलब्धता, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, कुशल मानव संसाधन और विकसित हो रहे औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रमुखता से सामने रखा गया।

125 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से बढ़ा भरोसा

IIFF 2026 के दौरान बिहार सरकार और दो निवेशकों के बीच कुल **125 करोड़ के निवेश प्रस्तावों** के लिए समझौता ज्ञापन हुए। इन परियोजनाओं से लगभग **1,800 प्रत्यक्ष रोजगार** सृजित होने की उम्मीद है।

Lehar Footwear Private Limited के साथ **100 करोड़** के प्रस्तावित निवेश से करीब **1,500 प्रत्यक्ष रोजगार** और **Patna Leather Garment** के **25 करोड़** के प्रस्तावित निवेश से लगभग **300 प्रत्यक्ष रोजगार** के अवसर बनने की संभावना है।

यह निवेश केवल दो औद्योगिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। इसके साथ कच्चे माल, कंपोनेंट्स, पैकेजिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और सहायक उद्योगों के लिए भी नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

महवल में तैयार हो रहा औद्योगिक आधार

बिहार के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में **मुजफ्फरपुर के महवल में मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज पार्क** विकसित किया गया है। निवेशकों के लिए प्लॉट लीज आधार पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योगों को आधारभूत सुविधाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा से मुक्त कर उत्पादन गतिविधियों को तेजी से शुरू करने का अवसर देना है।

> **निवेश का यह नया अध्याय यदि कौशल, गुणवत्ता और निर्यात की मजबूत रणनीति से जुड़ता है, तो "मेड इन बिहार" फुटवियर आने वाले समय में राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकता है।**

फुटवियर और लेदर उद्योग जैसे रोजगार-प्रधान क्षेत्र के लिए यह पहल विशेष महत्व रखती है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर विनिर्माण गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल सकता है।

नीतियों से निवेश तक— सरकार का फोकस

बिहार की उद्योग एवं खेल मंत्री **सुश्री श्रेयसी सिंह** ने निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने श्रमशक्ति, संसाधनों, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल वातावरण को बिहार की प्रमुख ताकत बताया।

वहीं, उद्योग विभाग के सचिव **श्री कुंदन कुमार** ने औद्योगिक नीतियों, भूमि उपलब्धता, प्रोत्साहन योजनाओं, लॉजिस्टिक्स और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

यह संदेश स्पष्ट है कि बिहार औद्योगिक निवेश को केवल आकर्षित करने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि **तेज स्वीकृति, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाजनक कारोबारी वातावरण** के माध्यम से निवेश को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ■

कौशल और तकनीक बनेगी विकास की ताकत

फुटवियर उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता, डिजाइन, तकनीक और कुशल मानव संसाधन की भूमिका निर्णायक होती है। FDDI के प्रबंध निदेशक **श्री विवेक शर्मा** ने भी कौशल विकास, डिजाइन और आधुनिक तकनीक के महत्व को रेखांकित किया।

बिहार के लिए यह क्षेत्र विशेष अवसर लेकर आया है। रोजगार-प्रधान विनिर्माण उद्योगों में बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जा सकता है।

निवेशकों के अनुभव ने बढ़ाया विश्वास

राज्य में निवेश कर रहे उद्योग प्रतिनिधियों ने भी सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक नीतियों की सराहना की। उद्योग जगत की यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि बिहार में औद्योगिक वातावरण को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत हो रहा है। कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स के प्रबंध निदेशक श्री धनेश प्रसाद और कॉम्फी फुटवियर के निदेशक श्री जयकांत ने राज्य में निवेश के अनुभव साझा करते हुए सकारात्मक औद्योगिक वातावरण की ओर ध्यान आकर्षित किया।

फुटवियर सेक्टर से रोजगार का बड़ा अवसर

फुटवियर एवं लेदर उद्योग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसका रोजगार-प्रधान होना है। उत्पादन इकाइयों के साथ डिजाइन, कटिंग, सिलाई, फिनिशिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

इस दृष्टि से बिहार में फुटवियर सेक्टर का विस्तार **"निवेश से रोजगार और रोजगार से स्थानीय अर्थव्यवस्था"** के मॉडल को मजबूत कर सकता है।

बिहार की औद्योगिक कहानी में नया अध्याय

IIFF 2026 में बिहार की भागीदारी को केवल एक प्रदर्शनी में राज्य की उपस्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह बिहार की उस नई औद्योगिक सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें **निवेश, विनिर्माण, कौशल, रोजगार और निर्यात** को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है।

125 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और करीब **1,800 प्रत्यक्ष रोजगार** की संभावनाएं शुरुआत भर हैं। यदि औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, लॉजिस्टिक्स और निवेश सुविधाओं को निरंतर मजबूती मिलती है, तो बिहार आने वाले वर्षों में फुटवियर एवं लेदर विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर सकता है।

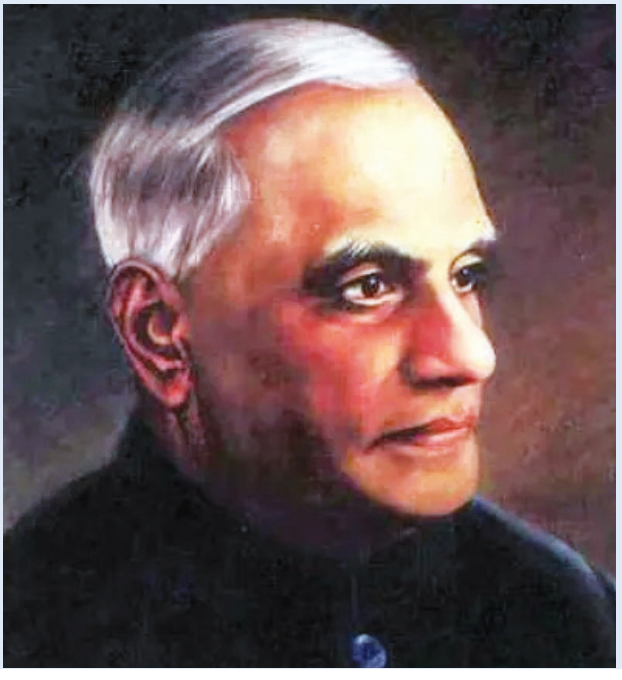
बिहार की औद्योगिक यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। फुटवियर और लेदर सेक्टर में आया निवेश यह दर्शाता है कि राज्य अपनी पारंपरिक आर्थिक पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक विनिर्माण और रोजगार-प्रधान उद्योगों की ओर कदम बढ़ा रहा है। महवल जैसे औद्योगिक क्लस्टर, निवेश-अनुकूल नीतियां और बढ़ती कनेक्टिविटी इस बदलाव की आधारशिला बन सकती हैं।

निवेश का यह नया अध्याय यदि कौशल, गुणवत्ता और निर्यात की मजबूत रणनीति से जुड़ता है, तो "मेड इन बिहार" फुटवियर आने वाले समय में राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकता है। ■

वी. वी. गिरि: भारत के श्रम आंदोलन की वह आवाज, जिसने लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर तक बनाई अपनी पहचान

'श्रमिक केवल उत्पादन की शक्ति नहीं, राष्ट्र की प्रगति का साझेदार है' — वी. वी. गिरि की विरासत आज भी प्रासंगिक

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर समाज, श्रमिक वर्ग और राष्ट्र—तीनों के हितों को एक साथ आगे बढ़ाने



का प्रयास किया। **वराहगिरी वेंकट गिरि (वी. वी. गिरि)** उन्हीं महान व्यक्तित्वों में शामिल हैं।

श्रमिक अधिकारों के प्रबल समर्थक, ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख चेहरा और स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वी. वी. गिरि ने सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जन्म **10 अगस्त 1894** को हुआ था। श्रमिक हितों के लिए उनका समर्पित जीवन भारतीय श्रम आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

श्रमिक आंदोलन से शुरू हुआ राष्ट्रसेवा का सफर

वी. वी. गिरि का सार्वजनिक जीवन उस दौर में आगे बढ़ा, जब भारत में औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों को लेकर जागरूकता तेजी से विकसित हो रही थी। उन्होंने श्रमिक संगठनों के माध्यम से कामगारों की आवाज को मजबूत करने का प्रयास किया।

उनकी दृष्टि में श्रमिकों का कल्याण केवल वेतन और रोजगार तक सीमित विषय नहीं था। वे **सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक भागीदारी और बेहतर औद्योगिक संबंधों** को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे।

यही सोच आगे चलकर उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान बनी।

संवाद और सामंजस्य को माना औद्योगिक प्रगति की कुंजी

भारत जैसे विशाल और विविध औद्योगिक देश में श्रमिक और नियोक्ता के बीच संतुलित संबंध आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वी. वी. गिरि ने औद्योगिक विवादों के समाधान में संवाद, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिकों की भागीदारी जैसे विचारों को महत्व दिया।

उनकी सोच का मूल संदेश था कि **उद्योग की सफलता और श्रमिकों की खुशहाली एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए लक्ष्य हैं।**

आज जब भारत विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, स्टार्टअप और नई तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब यह दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

राष्ट्रपति पद तक पहुंची श्रमिक हितों की आवाज

वी. वी. गिरि ने विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। वे **उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल** रहे तथा बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने।

इसके बाद वर्ष 1969 में वे भारत के चौथे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

यह यात्रा इस बात का प्रतीक थी कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक सरोकारों और श्रमिक हितों से जुड़े व्यक्ति भी राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकते हैं।

'राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक अर्थ तभी है, जब विकास की धारा में श्रमिक का सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो।'

आज के भारत में क्यों महत्वपूर्ण है उनकी विरासत?

21वीं सदी का भारत तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिग इकोनॉमी और बदलते रोजगार स्वरूपों ने श्रम जगत के सामने नई संभावनाओं के साथ नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं।

ऐसे दौर में वी. वी. गिरि की विरासत हमें तीन महत्वपूर्ण संदेश देती है—

पहला—**श्रमिक की गरिमा सर्वोपरि है।**

रोजगार केवल आय का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से भी जुड़ा है।

दूसरा—संवाद से मजबूत होते हैं औद्योगिक संबंध।

नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग से उद्योग अधिक स्थिर एवं उत्पादक बन सकते हैं।

तीसरा—कौशल और सामाजिक सुरक्षा भविष्य की आधारशिला हैं।

बदलती अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को नए कौशल, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना समावेशी विकास के लिए आवश्यक है।

विरासत से भविष्य की ओर

आज भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, MSME विकास, कौशल भारत, स्टार्टअप और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

इस विकास यात्रा में श्रमिक केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि **राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के सक्रिय भागीदार** हैं।

वी. वी. गिरि का जीवन इसी विचार को मजबूती देता है कि **राष्ट्र निर्माण की इमारत मजबूत तभी होगी, जब उसकी नींव में श्रम, सम्मान और सामाजिक न्याय का संतुलन कायम रहे।**

एक प्रेरक विरासत

वी. वी. गिरि का जीवन संघर्ष से सफलता और श्रमिक आंदोलन से राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की प्रेरक यात्रा है। उनकी जयंती केवल एक महान व्यक्तित्व को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि भारत के श्रमिक वर्ग के योगदान और सम्मान को रेखांकित करने का भी अवसर है। ■

विशेष

बच्चों का बचपन, स्क्रीन नहीं— संवेदनशील प्रशासन की नई पहल

गौतमबुद्ध नगर में तकनीक और बचपन के बीच संतुलन की राह दिखा रहीं **जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम**



यह पहल एक ऐसे संवेदनशील प्रशासन की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो विकास के साथ-साथ बच्चों की आंखों की रोशनी, उनके मन की खुशी और उनके बचपन की सहजता को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है।

आज का बच्चा तकनीक के दौर में जन्म ले रहा है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास उसकी शिक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि **तकनीक बच्चों के विकास का माध्यम बने या उनका बचपन ही स्क्रीन में सिमट जाए?**

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की ओर से बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश इसी संवेदनशील सोच का परिचायक हैं। जिलाधिकारी **श्रीमती मेधा रूपम** की पहल में केवल प्रशासनिक अनुशासन नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, आंखों की सुरक्षा और उनके सहज बचपन की चिंता दिखाई देती है।

तकनीक शिक्षा का साधन बने, बोझ नहीं

डिजिटल शिक्षा ने सीखने के नए रास्ते खोले हैं। वीडियो, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए विषयों को अधिक रोचक और सहज बना सकते हैं। लेकिन शिक्षा में तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है, जब वह **बच्चे की जरूरत के अनुसार हो, उसकी जगह लेने के लिए नहीं।** लगातार और अनियंत्रित स्क्रीन उपयोग से आंखों में थकान, नींद प्रभावित होना, शारीरिक सक्रियता में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और सामाजिक संवाद पर असर जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम को सीमित करना बच्चों को तकनीक से दूर करना नहीं, बल्कि **तकनीक के स्वस्थ और संतुलित उपयोग की आदत विकसित करना है।**

बच्चों को तकनीक दें, लेकिन साथ में मैदान भी दें।
उन्हें डिजिटल ज्ञान दें, लेकिन किताब भी दें।
उन्हें स्क्रीन दें, लेकिन संवाद भी दें।
उन्हें स्मार्ट क्लास दें, लेकिन खुला आसमान भी दें।

विद्यालयों के लिए संदेश—स्मार्ट क्लास का अर्थ लगातार स्क्रीन नहीं

स्मार्ट क्लास का उद्देश्य बच्चों को हर समय स्क्रीन के सामने बैठाना नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और सहभागितापूर्ण बनाना है।

विद्यालयों में डिजिटल माध्यम के साथ-साथ **ब्लैकबोर्ड, किताब, लेखन, चर्चा, खेल, प्रयोग, कला, समूह गतिविधियां और शिक्षक के साथ प्रत्यक्ष संवाद** को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए।

यानी— **स्मार्ट क्लास वह है जहां तकनीक शिक्षक की मदद करे, शिक्षक और बच्चे के संवाद की जगह न ले।**

हर बच्चे की जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी

बच्चों के स्क्रीन टाइम को संतुलित करने की जिम्मेदारी केवल विद्यालय की नहीं है। इसमें अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन—सभी की समान भूमिका है। बच्चों को

> **“स्क्रीन सीमित हो, सीखने की दुनिया असीमित हो—यही स्वस्थ बचपन की सही दिशा है।”**

केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि 'स्क्रीन कम देखो।' जरूरी है कि उन्हें **खेलने, पढ़ने, बातचीत करने, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और प्रकृति के साथ समय बिताने के पर्याप्त अवसर** भी दिए जाएं। यही वह दृष्टिकोण है जो किसी प्रशासनिक दिशा-निर्देश को महज आदेश से आगे ले जाकर **बाल-केंद्रित पहल** बनाता है।

दिशा-निर्देश से आगे—संवेदनशील सोच

गौतमबुद्ध नगर जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में तकनीक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में बच्चों के लिए डिजिटल संतुलन की बात करना भविष्य की पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक है। जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम की इस पहल का सकारात्मक पक्ष यही है कि इसमें बच्चों को केवल 'विद्यार्थी' के रूप में नहीं, बल्कि **संवेदनशील मन, स्वस्थ शरीर और सपनों से भरे भविष्य के नागरिक** के रूप में देखा गया है। यह पहल हमें याद दिलाती है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल स्मार्ट स्कूल और डिजिटल सुविधाएं नहीं, बल्कि **स्वस्थ, खुश और संवेदनशील बच्चे** भी हैं।

एक स्क्रीन कम, एक संवाद ज्यादा

आज आवश्यकता तकनीक को रोकने की नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग की है। बच्चे स्क्रीन पर दुनिया देख सकते हैं, लेकिन उन्हें दुनिया **जीने का अवसर** भी मिलना चाहिए।

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन का यह प्रयास इसी संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है— **जहां तकनीक बच्चों के हाथ में हो, लेकिन उनका बचपन स्क्रीन के हाथ में न चला जाए।** ■

बीकानेर हाउस में संस्कृति के रंग

तीजोत्सव 2026 ने दिल्ली को कराया राजस्थान की लोक परंपराओं से रूबरू

परंपरा, पर्यटन और हस्तशिल्प का संगम बना दस दिवसीय तीजोत्सव



राजस्थान की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और रंग-बिरंगी जीवनशैली को राजधानी दिल्ली के करीब लाने की एक सराहनीय पहल के रूप में बीकानेर हाउस में **‘तीजोत्सव 2026’** का शुभारंभ हुआ। दस दिवसीय यह आयोजन केवल पारंपरिक पर्व का उत्सव नहीं, बल्कि **राजस्थानी कला, लोकसंगीत, हस्तशिल्प, खान-पान और महिला सहभागिता को एक मंच देने वाला सांस्कृतिक महोत्सव** बनकर सामने आया।

राजस्थान के प्रमुख आवासीय आयुक्त **श्री रोहित कुमार** ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया तथा तीज माता की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन दिल्ली में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ-साथ देश की राजधानी के नागरिकों को राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का प्रभावी माध्यम हैं।

तीज माता की सवारी ने बांधा सांस्कृतिक समां

उत्सव का प्रमुख आकर्षण तीज माता की पारंपरिक सवारी रही। सुसज्जित पालकी में तीज माता को विराजमान कर चार कहारों द्वारा पारंपरिक रूप से परिसर में सवारी निकाली गई। लगभग **51 महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा** के साथ इसमें सहभागिता की। राजस्थानी परिधानों में सजी महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ तीज माता की आराधना कर पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

लोककलाकारों द्वारा मशक वादन और कच्छी घोड़ी जैसी प्रस्तुतियों ने सवारी को और आकर्षक बनाया। अलग-अलग क्षेत्रों से आए महिला-पुरुषों की सहभागिता ने इस आयोजन को **लोक परंपरा और आधुनिक महानगरीय जीवन के बीच सांस्कृतिक सेतु** का रूप दिया।

लोककला के संरक्षण का जीवंत मंच

तीजोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोककलाकारों ने अपनी विशिष्ट कला का प्रदर्शन किया। बीकानेर, टोंक, चूरू, जोधपुर, अजमेर, बारां, डीग और अलवर के कलाकारों ने **मशक वादन, कच्छी घोड़ी, भोपा गायन, खड़ताल, चरी, चकरी, चंग-ढप, घूमर, कालबेलिया, मयूर नृत्य और फूलों की होली** जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों को राजस्थान की विविध लोक परंपराओं से परिचित कराया। यह पहल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि लोककलाओं को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर उन्हें **नई पीढ़ी और देश की राजधानी के व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर** दिया गया।

हस्तशिल्प को बाजार से जोड़ने की सकारात्मक पहल

तीजोत्सव में राजीविका और रूडा से जुड़े स्वयं सहायता समूहों एवं हस्तशिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इससे ग्रामीण और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों की सीधी प्रस्तुति और संभावित बाजार उपलब्ध कराने का अवसर मिल रहा है।

राजस्थानी हस्तशिल्प को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए **'राजसखी' ऐप/पोर्टल** जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों को देश-दुनिया के संभावित ग्राहकों तक



पहुंचा सकते हैं। इससे **'लोकल से ग्लोबल'** की अवधारणा को भी मजबूती मिलती है।

महिला सशक्तिकरण और लोक अर्थव्यवस्था का संगम

तीजोत्सव की एक उल्लेखनीय विशेषता महिला सहभागिता भी रही। मंगल कलश यात्रा और तीज माता की आराधना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने जहां परंपरा को जीवंत रखा, वहीं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री ने **महिला उद्यमिता और स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण** को भी मंच प्रदान किया।

ऐसे आयोजन यह संदेश देते हैं कि संस्कृति केवल विरासत नहीं, बल्कि **रोजगार, उद्यमिता, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार** भी बन सकती है।



पर्यटन और संस्कृति को मिला नया आयाम

राजस्थान के लोकव्यंजनों, हस्तनिर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराकर तीजोत्सव ने दिल्लीवासियों के लिए राजस्थान को अनुभव करने का अवसर प्रदान किया है। यह आयोजन **सांस्कृतिक पर्यटन** को बढ़ावा देने के साथ राजस्थान की विविध पहचान को राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुत करने की दिशा में प्रभावी पहल है।

परंपरा से प्रगति की ओर

24 अगस्त तक चलने वाला यह तीजोत्सव इस बात का उदाहरण है कि पारंपरिक उत्सवों को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। एक ओर जहां तीज माता की सवारी, मंगल गीत और लोकनृत्य राजस्थान की सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हैं, वहीं हस्तशिल्प बिक्री, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल बाजार जैसी पहलें इन्हें **आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ती हैं।**

'तीजोत्सव 2026' इस संदेश के साथ अपनी पहचान बनाता है कि संस्कृति को संरक्षित करने का सबसे बेहतर तरीका उसे समाज के बीच जीवंत रखना है—और जब संस्कृति के साथ पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था जुड़ती है, तो परंपरा विकास का माध्यम भी बन जाती है। ■





हरियाणा का नया संदेश—
'नवाचार को अवसर, उद्यमी को सहारा और युवाओं को आत्मनिर्भरता।'

हरियाणा में स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार

महिला उद्यमिता, निवेश और नवाचार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए **हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022** में व्यापक पूरक प्रावधानों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुए इस निर्णय का उद्देश्य युवाओं, महिला उद्यमियों और नवाचार आधारित व्यवसायों को बेहतर वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है।

महिला स्टार्टअप को विशेष लाभ

महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को एक वर्ष के लिए लीज किराए पर **50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख** तक मिलेगी। साथ ही सात वर्ष तक **शुद्ध SGST की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति** का प्रावधान है। सामान्य स्टार्टअप को सात वर्ष तक SGST की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलेगी।

निवेश से बाजार तक सरकार बनेगी भागीदार

टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एवं ट्रांसफर के लिए **10 लाख तक सहायता,** गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप को **5 लाख और महिला स्टार्टअप को 7 लाख** सालाना तक सहायता दी जाएगी।

निजी या एंजल निवेश से जुटाए गए प्रत्येक **25 लाख पर 25 लाख तक मैचिंग ग्रांट** का प्रावधान भी किया गया है।

H-Hub और सरकारी खरीद से मिलेगा नया बाजार

हरियाणा में विश्वस्तरीय '**H-Hub**' इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। वहीं सरकारी खरीद का **10 प्रतिशत हिस्सा पात्र हरियाणा आधारित स्टार्टअप** के लिए आरक्षित किया जाएगा। कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा स्टार्टअप के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर **10 लाख तक मैचिंग ग्रांट** का प्रावधान है।

युवा प्रतिभा और डिजिटल स्टार्टअप पर जोर

विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को स्टार्टअप अप्रेंटिसशिप से जोड़ने के साथ पात्र स्टार्टअप को वजीफे की 50 प्रतिशत लागत की प्रतिपूर्ति मिलेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग एवं डेटा स्टोरेज पर **75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति,** अधिकतम **2.5 लाख प्रतिवर्ष,** पांच वर्ष तक दी जाएगी। ■

हरियाणा की नई पहल आइडिया से निवेश और निवेश से रोजगार तक स्टार्टअप की पूरी यात्रा को मजबूत करने का प्रयास है। महिला उद्यमिता, निजी निवेश, सरकारी खरीद, तकनीकी सहयोग और H-Hub जैसी पहलें प्रदेश में एक मजबूत नवाचार संस्कृति विकसित कर सकती हैं।

दूध से समृद्धि की नई राहः सरगुजा और बस्तर में डेयरी क्रांति को रफ्तार

महिला दुग्ध उत्पादकों की बढ़ती भागीदारी से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ में डेयरी क्षेत्र को ग्रामीण आय और रोजगार का मजबूत आधार बनाने की दिशा में नई पहल तेज हो रही है। विशेष रूप से **सरगुजा और बस्तर संभाग** में डेयरी विकास पर फोकस बढ़ाया गया है। उद्देश्य है—दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और महिलाओं को डेयरी अर्थव्यवस्था से अधिक मजबूती से जोड़ना।

राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में डेयरी क्षेत्र की प्रगति, अधोसंरचना, मानव संसाधन तथा भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। बस्तर संभाग के सात जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अनुसूचित जनजाति परिवार पशुपालन से जुड़े हैं। यहां करीब **88 प्रतिशत गायें स्थानीय नस्ल** की हैं। ऐसे में पशु पोषण, स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और वैज्ञानिक पशुपालन के जरिए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

चिलिंग सेंटर से मजबूत हो रही दूध की सप्लाई चेन

सरगुजा संभाग में एनडीडीबी के सहयोग से जशपुर और बलरामपुर में चिलिंग सेंटर शुरू किए गए हैं। जशपुर में **2 हजार लीटर** और बलरामपुर में **5 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता** के चिलिंग सेंटर दुग्ध संग्रहण एवं संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं।

वर्तमान में **45 मिल्क कलेक्शन सेंटरों** के माध्यम से प्रतिदिन लगभग **3,500 लीटर दूध** एकत्र किया जा रहा है। इस व्यवस्था से **1,500 से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक** जुड़ी हैं। यह केवल दूध संग्रहण की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय और स्थानीय स्तर पर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सीधे बैंक खाते में भुगतान से बढ़ा भरोसा

डेयरी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था। दुग्ध उत्पादकों के बिल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और उत्पादकों को उनके दूध का भुगतान समय पर मिलने का भरोसा मजबूत होता है।





छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पहले से ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। अब वैज्ञानिक पशुपालन, बेहतर नस्ल, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक संग्रहण केंद्र और संगठित विपणन व्यवस्था के साथ इसे अधिक लाभकारी व्यवसाय में बदलने की कोशिश हो रही है।

डेयरी बनेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया आधार

छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पहले से ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। अब वैज्ञानिक पशुपालन, बेहतर नस्ल, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक संग्रहण केंद्र और संगठित विपणन व्यवस्था के साथ इसे अधिक लाभकारी व्यवसाय में बदलने की कोशिश हो रही है।

यदि दूध उत्पादन से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी श्रृंखला को मजबूत किया जाता है, तो इसका लाभ केवल पशुपालकों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे **महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उद्यमिता और गांवों की अर्थव्यवस्था** को भी नई गति मिल सकती है।

सरगुजा और बस्तर में डेयरी विकास का यह मॉडल आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में **'दूध से आय और आय से आत्मनिर्भरता'** की नई कहानी लिख सकता है। ■

पक्के घर से पक्के विश्वास तक— बिहार के गांवों में विकास की नई तस्वीर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने बदली लाखों परिवारों की जिंदगी, आत्मसम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद को मिली मजबूत छत





बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कहानी अब सिर्फ सड़कों और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है। एक पक्का घर गरीब परिवार के लिए सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार **में 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों** के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य को **13,427 करोड़ रुपये की सहायता** मिलने की जानकारी दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव की उम्मीद और मजबूत हुई है।

कार्यक्रम के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण हुए **2 लाख 35 हजार आवासों के गृह प्रवेश** और लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपने जैसी पहल ने इस बदलाव को उत्सव का रूप दिया। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच बिहार के गरीब परिवारों के लिए **50 लाख पक्के मकानों का आवंटन** किया जा चुका है, जबकि वर्ष 1986 से 2014 तक इंदिरा आवास योजना के तहत 30 लाख पक्के मकान बनाए गए थे।

जब विकास की योजनाएं गांव के अंतिम परिवार तक पहुंचती हैं, तो केवल घर नहीं बनते, बल्कि बेहतर जीवन, सम्मान और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव भी मजबूत होती है।

इस पहल का महत्व केवल एक मकान मिलने तक सीमित नहीं है। अपने घर की छत परिवार को सुरक्षा के साथ सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी देती है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास को मानवीय गरिमा से जोड़ने वाली योजनाएं गांवों की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

बिहार में ग्रामीण विकास की एक और सकारात्मक तस्वीर **स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों** के माध्यम से सामने आ रही है। राज्य में **1 करोड़ 81 लाख जीविका दीदियां** स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और इनमें **30 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी'** बन चुकी हैं। यह महिला आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आता है।

ग्रामीण विकास को रोजगार, आवास और महिला सशक्तीकरण से जोड़ने वाली ऐसी पहलें बताती हैं कि विकास तब अधिक प्रभावी बनता है, जब उसका सीधा लाभ गांव के सामान्य परिवार तक पहुंचे। पक्का घर जहां सुरक्षा का आधार बनता है, वहीं स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ■



पलायन से रिवर्स पलायन की ओर उत्तराखण्ड

गांवों में रोजगार, स्वरोजगार और बाजार की नई संभावनाएं तैयार करने पर सरकार का जोर

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पलायन की चुनौती को अब अवसर में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने अपना फोकस और मजबूत किया है। लक्ष्य केवल पलायन को रोकना नहीं, बल्कि **गांवों को ऐसी आर्थिक और सामाजिक ताकत देना है कि लोग रोजगार और बेहतर आजीविका की तलाश में गांव छोड़ने के बजाय वापस लौटने का निर्णय लें।**

मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में इसी व्यापक दृष्टिकोण पर मंथन हुआ। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और रि**वर्स पलायन को गति देने के लिए विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन** पर विशेष जोर दिया गया।

रिवर्स पलायन के लिए समन्वित रणनीति

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से **समन्वित एवं परिणामोन्मुखी प्रयास** करें। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ों में पलायन की चुनौती किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बाजार, डिजिटल कनेक्टिविटी और आजीविका— इन सभी क्षेत्रों में बेहतर अवसरों का निर्माण ही गांवों को टिकाऊ बनाएगा।

गांव में ही रोजगार की नई जमीन

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय कौशल की भरपूर संभावनाएं हैं। पहाड़ी कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्यम ग्रामीण युवाओं के लिए आय के नए साधन बन सकते हैं। सरकार का जोर अब इसी क्षमता को **रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर** है। यदि स्थानीय

युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार उपलब्ध हो, तो उनका हुनर गांव में ही आर्थिक गतिविधि को जन्म दे सकता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ गांव की चौखट तक

रिवर्स पलायन की राह में एक महत्वपूर्ण पहलू योजनाओं की आसान पहुंच भी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी **सरल एवं प्रभावी तरीके से गांव स्तर** पर उपलब्ध कराई जाए।

योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। यह बदलाव ग्रामीण उद्यमिता को गति देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सही जानकारी और आसान प्रक्रिया मिलने पर अनेक ऐसे युवा और परिवार भी सरकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं, जो जानकारी या प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण अब तक पीछे रह जाते हैं।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार

उत्तराखण्ड के गांवों की सबसे बड़ी ताकत उनके स्थानीय उत्पाद हैं। पर्वतीय अनाज, मसाले, फल, शहद, जड़ी-बूटियां, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद देश के बड़े बाजारों में अपनी पहचान बना सकते हैं।

इसके लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। **गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमाणन और बाजार तक पहुंच** को मजबूत करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है।

यदि गांव में उत्पाद तैयार हो और उसका बाजार देश-दुनिया तक पहुंचे, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिल सकता है।

प्रवासी पंचायतों से संवाद की नई पहल

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा विभिन्न जनपदों में आयोजित **प्रवासी पंचायतों और पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों** के माध्यम से प्रवासियों और ग्रामीण समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड से बाहर रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के पास अनुभव, पूंजी, नेटवर्क और बाजार की समझ है। यदि इन संसाधनों को गांवों की स्थानीय क्षमता से जोड़ा जाए तो **रिवर्स पलायन केवल घर लौटने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि नए निवेश और नए उद्यमों की शुरुआत** भी बन सकता है।



रिवर्स पलायन की यह यात्रा केवल गांवों की वापसी नहीं— उत्तराखण्ड की जड़ों, संसाधनों और संभावनाओं की ओर वापसी है।

'गांव की ओर वापसी' बने आर्थिक बदलाव का अभियान

रिवर्स पलायन को सफल बनाने के लिए गांव में केवल रोजगार नहीं, बल्कि **सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका** जरूरी है। जब किसी युवा को अपने गांव में उद्यम शुरू करने, स्थानीय संसाधनों से कमाई करने और अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, तब गांव में रहना मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प बनेगा।

उत्तराखण्ड की पहाड़ी अर्थव्यवस्था में यही बदलाव आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है।

मजबूत गांव, मजबूत उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री का यह संदेश कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि गांवों में **बेहतर आजीविका, सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करने से संभव होगा,** इस पूरी रणनीति की दिशा स्पष्ट करता है।

उत्तराखण्ड के लिए रिवर्स पलायन केवल जनसंख्या के आंकड़ों में बदलाव नहीं है। यह **बंद होते घरों में फिर से चूल्हा जलने, खेतों में फिर से खेती लौटने, स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलने और युवाओं के सपनों को अपने गांव में आकार मिलने** की कहानी है।

यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और बाजार से जुड़ाव इसी गति से आगे बढ़ता है, तो आने वाले समय में उत्तराखण्ड के पहाड़ **पलायन की पीड़ा से निकलकर ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के नए मॉडल** के रूप में देश के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं। ■

गांव की ताकत से आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की नई कहानी

उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़कर पलायन रोकने की दिशा में बढ़ते कदम

उत्तराखण्ड की पहचान केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी संस्कृति से ही नहीं, बल्कि यहां के मेहनतकश लोगों, हुनरमंद महिलाओं और युवा उद्यमियों से भी है। आज प्रदेश के गांवों में आत्मनिर्भरता की एक नई तस्वीर आकार ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने तथा स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है।

इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में **'मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना'** महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आई है। योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में **13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग** दिया जा चुका है, जबकि **8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों** को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है।

महिला शक्ति बनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई पहचान

उत्तराखण्ड की मातृशक्ति आज पारंपरिक हुनर को आधुनिक उद्यम में बदल रही है। पहाड़ी मसालों, मंडुवा, झंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प, ऊनी उत्पादों और स्थानीय कला को बाजार की जरूरत के अनुरूप उत्पादों में बदलकर महिलाएं न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में **5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।** इनमें से **3 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी'** बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। यह आंकड़ा केवल आर्थिक सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और बदलती भूमिका की कहानी भी कहता है।



तेरहगांव में बनेगा राज्य स्तरीय विपणन केंद्र

ग्रामीण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने देहरादून के **तेरहगांव, आई.टी. पार्क के निकट राज्य स्तरीय विपणन केंद्र** स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जिलों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

यह पहल उन ग्रामीण उत्पादकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके पास बेहतर उत्पाद तो हैं, लेकिन उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन और नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। विपणन केंद्र ऐसे उत्पादों को पहचान, बाजार और संभावित बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में अहम कड़ी बन सकता है।

'हाउस ऑफ हिमालयाज' से लोकल उत्पादों को ग्लोबल पहचान

उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को एक मजबूत पहचान देने के उद्देश्य से **'हाउस ऑफ हिमालयाज'** को अंब्रेला ब्रांड के रूप में विकसित किया गया है। यह पहल स्थानीय उत्पादों को संगठित ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू



ग्लोबल' की भावना के साथ यदि पहाड़ी उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, आधुनिक मार्केटिंग और डिजिटल बाजार उपलब्ध होता है, तो ये उत्पाद देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उत्तराखण्ड की विशिष्ट पहचान बन सकते हैं।

गांव मजबूत होंगे तो उत्तराखण्ड मजबूत होगा

ग्रामीण उद्यमिता का उद्देश्य केवल रोजगार और आय बढ़ाना नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य **पलायन की चुनौती का समाधान** भी है। जब गांव में ही रोजगार, स्वरोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होंगे, तो युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने की मजबूरी कम होगी।

इसी दिशा में **'ग्रामोत्थान परियोजना' (रीप)** के माध्यम से अति-निर्धन ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने और गांवों में रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशिक्षण से बाजार तक—उद्यमी को मिल रहा पूरा सहयोग

'मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना' की खासियत यह है कि ग्रामीण उद्यमियों को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखा गया है।व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए **प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग और बाजार से जोड़ने** पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 13 जिलों में **'मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल'** आयोजित किए जाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे और पात्र लोग उनका लाभ उठा सकें। प्रचार वैन के माध्यम से योजनाओं की जानकारी समाज के



उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब सहायता की नहीं, अवसर और बाजार की ओर बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, युवा रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और स्थानीय उत्पाद अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े बाजार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि यदि स्थानीय हुनर को प्रशिक्षण, पूंजी, तकनीक और बाजार का साथ मिले, तो पहाड़ के गांव आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास इस अभियान को और व्यापक बना रहा है।

स्थानीय उत्पादों में छिपी है उत्तराखण्ड की आर्थिक शक्ति

उत्तराखण्ड के गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय हुनर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी पूंजी हैं। जरूरत इन्हें आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने की है। सरकार की वर्तमान पहलें इसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। **ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर** और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का उद्देश्य उत्पादक और बाजार के बीच की दूरी कम करना है।

आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की राह गांवों से होकर जाती है—और इन गांवों में आज उद्यमिता की नई रोशनी दिखाई दे रही है। ■



UP for Global Growth: Innovation, Manufacturing and Exports' — उत्तर प्रदेश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम

उत्तर प्रदेश आज केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का सबसे सशक्त इंजन बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** के दूरदर्शी नेतृत्व में औद्योगिक विकास, निवेश, निर्यात, एमएसएमई संवर्धन तथा वैश्विक व्यापार को नई गति मिली है। इसी क्रम में **25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट** में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश **इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS)-2026** प्रदेश की औद्योगिक शक्ति और वैश्विक संभावनाओं का विराट प्रदर्शन बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** के **'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड'** के विजन को साकार करने वाला एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों, नवाचार, विनिर्माण क्षमता और निर्यात संभावनाओं को विश्व बाजार से जोड़ना है।



वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की दमदार उपस्थिति

इस वर्ष ट्रेड शो की **'UP for Global Growth: Innovation, Manufacturing and Exports'** रखी गई है, जो उत्तर प्रदेश की बदलती आर्थिक पहचान को दर्शाती है। आयोजन में **2,400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक B2B खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक B2C आगंतुकों तथा 85 देशों के 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों** की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापारिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास है।



निवेश, निर्यात और रोजगार को मिलेगा नया विस्तार

ट्रेड शो के माध्यम से **4,000 से अधिक एमओयू, लगभग 3,200 करोड़ के प्रस्तावित निवेश समझौते** तथा **13,500 करोड़ से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह आयोजन प्रदेश के एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए बाजारों के द्वार खोलेगा। इससे निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

विश्व के साथ बढ़ते आर्थिक संबंध

मुख्यमंत्री ने **सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, रूस** सहित अनेक देशों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और वैश्विक कंपनियों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगी तथा विदेशी निवेश को नई गति प्रदान करेगी।

सुव्यवस्थित आयोजन की व्यापक तैयारी

प्रदेश सरकार ट्रेड शो को विश्वस्तरीय बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रही है। अंतरराष्ट्रीय खरीदारों एवं उद्यमियों की सहायता के लिए **उद्यमी मित्रों** की तैनाती, स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की सहभागिता, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, आधुनिक पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं तथा **ईवी बसों** के संचालन जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष बल दिया गया है। इससे आगंतुकों को सहज, सुरक्षित और उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त होगा।

नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान

आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और निर्यातकों के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य बन चुका है। इंटरनेशनल ट्रेड शो–2026 इस परिवर्तन की सशक्त अभिव्यक्ति होगा, जहाँ स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान प्राप्त करेंगे, उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। ■



उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो–2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि 'नए उत्तर प्रदेश' की आर्थिक सोच, औद्योगिक आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा का जीवंत प्रतीक है। यह आयोजन निवेश, नवाचार, निर्यात और रोजगार के नए अध्याय लिखते हुए उत्तर प्रदेश को 'ग्लोबल ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

देवभूमि की नई विकास गाथा

सुशासन, निवेश, पर्यटन और रोजगार के साथ उत्तराखण्ड ने पकड़ी विकास की तेज रफ्तार



उत्तराखण्ड आज विकास की ऐसी राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां **पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, रोजगार, निवेश और पर्यटन** को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** ने *The Economic Times World Leaders Forum 2026* में राज्य की विकास यात्रा और भविष्य की प्राथमिकताओं को देश-दुनिया के सामने रखा।

निवेश के लिए तैयार हुआ नया उत्तराखण्ड

वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य की औद्योगिक पहचान को नई गति मिली है। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से **30 से अधिक नई नीतियां** लागू की गई हैं। सरकार का जोर एमओयू तक सीमित रहने के बजाय निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और उनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने पर है।

युवाओं को रोजगार, भर्ती में पारदर्शिता

रोजगार के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। पिछले पांच वर्षों में **34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति** दिए जाने का उल्लेख मुख्यमंत्री ने किया। भर्ती प्रक्रिया में सुधार और नकल विरोधी कार्रवाई से युवाओं के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

कनेक्टिविटी से विकास को नई उड़ान

उत्तराखण्ड में सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार विकास की बड़ी ताकत बन रहा है। **ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर** से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। देहरादून से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार भी पर्यटन और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है।

पंतनगर को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं के साथ प्रस्तावित **ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट** भी राज्य की आर्थिक क्षमता को मजबूत कर सकता है।

पर्यटन बनेगा सालभर रोजगार का आधार

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चारधाम, कांवड़ और आदि कैलाश यात्रा के साथ सरकार अब **विंटर टूरिज्म** को भी बढ़ावा दे रही है। हर्षिल-मुखवा जैसे क्षेत्रों को शीतकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से होमस्टे, होटल, ढाबे, परिवहन और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। इसका सीधा लाभ पहाड़ के युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को मिल सकता है।

सीमांत गांवों को 'प्रथम गांव' की पहचान

आदि कैलाश जैसे सीमांत क्षेत्रों में बढ़ता पर्यटन केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अवसर बन रहा है। सीमांत गांवों को बेहतर सड़क, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आजीविका सुविधाओं से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया जा रहा है।

एआई और इनोवेशन से भविष्य की तैयारी

उत्तराखण्ड ने नवाचार नीति के साथ **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी** को विकास की नई दिशा से जोड़ा है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

उत्तराखण्ड की विकास यात्रा का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि राज्य पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास और स्थानीय अवसरों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निवेश के साथ रोजगार, पर्यटन के साथ स्थानीय उद्यमिता, कनेक्टिविटी के साथ सीमांत विकास और तकनीक के साथ युवा शक्ति—यही समग्र दृष्टिकोण देवभूमि को नई आर्थिक पहचान दे सकता है।

अब लक्ष्य केवल पहाड़ों तक विकास पहुंचाना नहीं, बल्कि पहाड़ों में ही विकास के अवसर पैदा करना है।

'सुशासन की मजबूती, निवेश की गति और पर्यटन की शक्ति—उत्तराखण्ड लिख रहा है विकास की नई कहानी।'

विशेषः आगामी जनवरी 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए भी राज्य सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है, जो उत्तराखण्ड की धार्मिक पर्यटन क्षमता को और मजबूत करने का अवसर बनेगा। ■

पी एफ सी
PFC

(एक महारत्न कंपनी)

राष्ट्र की सशक्त संधारणीय संवृद्धि की ओर अग्रसर

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता

82,000 मेगावाट – सम्मिलित इक्विटी ऊर्जा क्षमता संवर्धन



उत्पाद एवं सेवाएं



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी)

www.pfcindia.com

राज्यस्तर भविष्य के लिए विश्वसनीय साथी

/pfcindia | /pfcindia | /pfcindia

MAJOR SD SINGH UNIVERSITY

Recognised by UGC under section 2(f) of UGC Act 1956

Farrukhabad, Uttar Pradesh

Inspiring **Minds...** Transforming **Lives...**



COURSE DETAILS

Faculty of Ayurveda	Duration
B.A.M.S (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	4.5 Yrs+ 1 Year compulsory rotatory intern
Faculty of Nursing	
B.Sc. Nursing	4 Years
Post Basic B.Sc. Nursing	2 Years
M.Sc. Nursing	2 Years
GNM	3 Years
ANM	2 Years
Diploma of Anesthesia & Operation Theatre Technology	2.5 Years
Faculty of Pharmacy	
B.Pharm. (Bachelor of Pharmacy)	4 Years
D.Pharm. (Diploma of Pharmacy)	2 Years
M.Pharm. (Master of Pharmacy)	2 Years

Faculty of Engineering & Technology	Duration
B.Tech. (Bachelor of Technology)	4 Years
M.Tech. (Master of Technology)	2 Years
BCA (Bachelor of Computer Application)	3 Years
MCA (Master of Computer Applications)	2 Years
PGDCA (Post Graduate Diploma in Com. Application)	1 Year
Diploma in Engineering	3 Years
Faculty of Law	
BA LL.B.	5 Years
BBA LL.B.	5 Years
LL.B.	3 Years
LL.M.	1 Years
LL.M.	2 Years
Faculty of Commerce & Management	
BBA (Bachelor of Business Administration)	3 Years
B.Com. (Bachelor of Commerce)(Hons.)	3 Years
MBA (Master of Business Administration)	2 Years
M.Com. (Master of Commerce)	2 Years

Faculty of Art, Science, Humanities	Duration
B.Sc. (Bachelor of Science) (Zoology / Botany / Chemistry / Physics / Math/	3 Years
M.Sc. (Master of Science) (Zoology / Botany / Chemistry / Physics / Math/	2 Years
B.A. (Bachelor of Arts)	3 Years
M.A. (Master of Art)	2 Years
B.LIS. (Bachelor of Library Information Science)	1 Year
M.LIs. (Master of Library Information Science)	1 Year
Faculty of Agriculture	
Diploma in Agriculture	1 Year
B.Sc. Agriculture	4 Years
M.Sc. Agriculture	2 Years
Faculty of Education	
D.El.Ed.	2 Years

Visit Us: www.msds.ac.in **Email: enquiry@msds.ac.in** **Contact Us: 7064-666-666**